RNI No. GUJHIN/2011/39228
GARVI GUJARAT
गरवी गुजरात
अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक
गरवी गुजरात

वर्ष : 15
अंक : 350
दि. 23.04.2026,
गुरुवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

देशभर में तपती धरती: उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत में लू का कहर, जनजीवन बेहाल

नई दिल्ली। देश के बड़े भूभाग पर गर्मी ने इस बार समय से पहले ही अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं और अब स्थिति धीरे-धीरे भयावह रूप लेती जा रही है। चिलचिलाती धूप, तेज़ गर्म हवाएं और लगातार बढ़ता तापमान मिलकर लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने ताजा चेतावनी जारी करते हुए साफ कहा है कि आने वाले चार से पांच दिनों तक उत्तर-पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत के अधिकांश हिस्सों में भीषण लू का प्रकोप जारी रहेगा। इस चेतावनी ने आम लोगों से लेकर प्रशासन तक को सतर्क कर दिया है, क्योंकि हालात ऐसे बनते दिख रहे हैं कि दिन के समय घर से बाहर निकलना किसी चुनौती से कम नहीं होगा।

सुबह होते ही सूरज की तपिश का असर महसूस होने लगता है और दोपहर तक स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि सड़कें सूनी नजर आने लगती हैं। बाजारों में रौनक कम हो गई है, कामकाजी लोग भी जरूरी कामों को टालने लगे हैं और स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति पर भी असर पड़ रहा है। कई शहरों में तापमान सामान्य से कई डिग्री ऊपर पहुंच चुका है, जिससे लोगों को झुलसा देने वाली गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टरों ने भी हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन के बढ़ते मामलों को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है।

मौसम विभाग के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली जैसे इलाकों में 24 और 25 अप्रैल को लू का असर और तेज़ होने की संभावना है। राजधानी दिल्ली में तो हालात पहले से ही चिंताजनक बने हुए हैं, जहां दिन के समय सड़कों पर निकलना बेहद कठिन हो गया है। हवा में नमी की कमी और सूखी गर्म हवाएं लोगों को बेहाल कर रही हैं। शाम के समय भी राहत नहीं मिल रही, जिससे लोगों की दिनचर्या पूरी तरह प्रभावित हो रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि यही स्थिति बनी रही तो बिजली की मांग भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकती है, जिससे पावर कट की समस्या और बढ़ सकती है।

उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में भी गर्मी का कहर चरम पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 23 से 25 अप्रैल तक और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 22 से 26 अप्रैल के बीच लू चलने की संभावना जताई गई है। राजस्थान के कई जिलों में तापमान 45 डिग्री के करीब पहुंचने की आशंका है, जिससे हालात और गंभीर हो सकते हैं। मध्य प्रदेश में भी 23 से 26 अप्रैल तक लू का असर बना रहेगा, जबकि विदर्भ और छत्तीसगढ़ में 24 से 27 अप्रैल के बीच भीषण गर्मी पड़ने की चेतावनी दी गई है। इन इलाकों में खेतों में काम करने वाले किसानों और मजदूरों के लिए यह स्थिति सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण बन गई है।

पूर्वी भारत भी इस गर्मी से अछूता नहीं है। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के गंगा के मैदानी इलाकों में भी तापमान तेजी से बढ़ रहा है और 22 से 23 अप्रैल के बीच लू का असर साफ देखा जा रहा है। दक्षिण बंगाल के कई जिलों में तो हालात ऐसे हैं कि लोग दिन के समय घरों में ही कैद रहने को मजबूर हो गए हैं। वहीं दूसरी ओर उत्तर बंगाल के इलाकों में मौसम ने अलग ही करवट ले ली है, जहां आंधी-तूफान और बारिश की संभावना बनी हुई है। दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और जलपाईगुड़ी जैसे पहाड़ी जिलों में 28 अप्रैल तक गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है, जिससे वहां रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है।

गर्मी का असर केवल दिन तक सीमित नहीं है, बल्कि रातें भी अब राहत देने में असमर्थ हो गई हैं। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और ओडिशा जैसे क्षेत्रों में गर्म रातों की स्थिति बन रही है, जहां तापमान रात के समय भी काफी अधिक बना हुआ है। इससे लोगों की नींद प्रभावित हो रही है और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ने लगी हैं। कोंकण और गोवा जैसे क्षेत्रों में भी रात के समय तापमान में कमी न आने से लोग परेशान हैं। तटीय राज्यों में उमस ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं, जहां पसीना और चिपचिपाहट से राहत मिलना मुश्किल हो गया है।

ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी, तमिलनाडु, केरल और तटीय कर्नाटक में 22 से 25 अप्रैल के बीच भारी उमस की स्थिति बनी रहने की संभावना है। यहां तापमान भले ही अत्यधिक न हो, लेकिन नमी के कारण गर्मी और ज्यादा महसूस हो रही है। लोग घरों में कूलर और एसी के सहारे राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लगातार बढ़ती गर्मी ने बिजली की खपत को भी बढ़ा दिया है, जिससे कई जगहों पर लोड बढ़ने की समस्या सामने आ रही है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार गर्मी का यह दौर सामान्य से अधिक तीव्र हो सकता है, जिसका मुख्य कारण बदलता जलवायु पैटर्न है। पर्यावरण में हो रहे बदलाव और बढ़ता तापमान अब सीधे तौर पर लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहा है। ऐसे में जरूरी है कि लोग सतर्क रहें और मौसम विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें। दिन के समय बाहर निकलने से बचें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और शरीर को ठंडा रखने के उपाय करें।

प्रशासन भी इस स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों में जुट गया है। कई राज्यों में अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है और आपातकालीन सेवाओं को मजबूत किया जा रहा है। स्कूलों के समय में बदलाव और निर्माण कार्यों में दोपहर के समय रोक लगाने जैसे कदम भी उठाए जा रहे हैं, ताकि लोगों को राहत मिल सके।

कुल मिलाकर, देश इस समय भीषण गर्मी और लू के एक कठिन दौर से गुजर रहा है, जिसने आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। आने वाले दिनों में यदि स्थिति और गंभीर होती है, तो यह चुनौती और बड़ी हो सकती है। ऐसे में सतर्कता, जागरूकता और सामूहिक प्रयास ही इस तपती परीक्षा से राहत दिला सकते हैं।

बंगाल की सियासत में तेज हुई बयानबाजी: अमित शाह का कांग्रेस पर बड़ा हमला, भाजपा के लिए किया जीत का दावा

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजनीतिक सरगर्मी के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दमदम में आयोजित एक चुनावी रैली में विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोलते हुए सियासी तापमान और बढ़ा दिया। अपने संबोधन में उन्होंने विशेष रूप से कांग्रेस और उसके वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए दावा किया कि इस बार कांग्रेस राज्य में अपना खाता भी नहीं खोल पाएगी। शाह ने कहा कि बंगाल की जनता अब कांग्रेस से पूरी तरह मोहभंग कर चुकी है और पार्टी का जनाधार लगभग समाप्त हो चुका है। उनके इस बयान ने न केवल कांग्रेस खेमे में हलचल मचा दी है, बल्कि राज्य की राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी तेज कर दिया है।

रैली के दौरान अमित शाह ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार पश्चिम बंगाल में अपनी पकड़ मजबूत कर रही है और आने वाले चुनावों में पार्टी का प्रदर्शन पहले से कहीं अधिक बेहतर होगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरते हुए कहा कि अब बंगाल में परिवर्तन की लहर चल पड़ी है और जनता विकास के एजेंडे के साथ खड़ी है। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि अन्य राजनीतिक दल केवल सत्ता हासिल करने के लिए राजनीति करते हैं, जबकि भाजपा का उद्देश्य देश और समाज का विकास है। शाह के इन बयानों से स्पष्ट संकेत मिलता है कि भाजपा इस बार बंगाल में पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है।

अपने भाषण में शाह ने राज्य की मौजूदा सरकार पर भी कड़ा प्रहार किया। उन्होंने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार पर कानून-व्यवस्था को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में हालात चिंताजनक हो चुके हैं और आम नागरिक खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में अपराध और अराजकता का माहौल है और प्रशासन इस पर नियंत्रण पाने में विफल रहा है। उन्होंने जनता से सीधा सवाल करते हुए कहा कि क्या वे ऐसे माहौल को स्वीकार कर सकते हैं, जहां कानून का राज कमजोर पड़ता जा रहा हो।

अमित शाह ने अपने संबोधन में समान नागरिक संहिता का मुद्दा भी उठाया और कहा कि भाजपा सत्ता में आने पर इसे लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इससे तीन तलाक और बहु-विवाह जैसी प्रथाओं पर रोक लगेगी और सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलेंगे। उन्होंने इस मुद्दे को सामाजिक न्याय और समानता से जोड़ते हुए जनता से भाजपा का समर्थन करने की अपील की। उनके इस बयान को चुनावी रणनीति के रूप में भी देखा जा रहा है, जो विभिन्न वर्गों के मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास हो सकता है। रैली के दौरान शाह ने यह भी दावा किया कि यदि राज्य में भाजपा की सरकार बनती है, तो मुख्यमंत्री एक स्थानीय बंगाली नेता होगा, जो राज्य की संस्कृति और भाषा से जुड़ा होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता ही राज्य की बागडोर संभालेंगे और एक नई दिशा में बंगाल को आगे बढ़ाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने महिलाओं को लेकर एक बड़ा वादा करते हुए कहा कि भाजपा सरकार बनने पर महिलाओं के खातों में हर महीने 3000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस घोषणा को महिला मतदाताओं को साधने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है।

शाह के इस पूरे भाषण ने बंगाल की राजनीति में नई बहस को जन्म दे दिया है। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस दोनों ही उनके आरोपों का जवाब देने की तैयारी में जुट गए हैं, जिससे आने वाले दिनों में सियासी बयानबाजी और तेज होने की संभावना है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह के तीखे बयान चुनावी माहौल को और गर्म करते हैं और मतदाताओं के बीच स्पष्ट ध्रुवीकरण पैदा करते हैं।

पश्चिम बंगाल में चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे-वैसे राजनीतिक दलों के बीच प्रतिस्पर्धा भी तेज होती जा रही है। सभी पार्टियां अपने-अपने तरीके से जनता को आकर्षित करने की कोशिश कर रही हैं। ऐसे में अमित शाह का यह बयान भाजपा की आक्रामक चुनावी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जो विपक्ष को घेरने और अपने समर्थन आधार को मजबूत करने के उद्देश्य से दिया गया है।

कुल मिलाकर, बंगाल की राजनीति इस समय एक अहम मोड़ पर खड़ी है, जहां हर बयान और हर वादा चुनावी परिणामों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि जनता किसके दावों और वादों पर भरोसा जताती है और किसे सत्ता की बागडोर सौंपती है।

मणिपुर में उबलता असंतोष: बंद और विरोध प्रदर्शनों से 12 जिलों में ठप जनजीवन

इंफाल। पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर एक बार फिर तनाव और अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है, जहां जातीय हिंसा और हालिया घटनाओं के विरोध में उभरा जनाक्रोश अब सड़कों पर साफ दिखाई दे रहा है। बुधवार को विभिन्न संगठनों द्वारा बुलाए गए बंद का असर राज्य के 16 में से 12 जिलों में व्यापक रूप से देखने को मिला, जिससे सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया। सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा, बाजार बंद रहे और लोगों को अपने घरों में ही रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालात ऐसे बन गए कि रोजमर्रा की गतिविधियां पूरी तरह ठप हो गईं और लोगों में असुरक्षा की भावना भी बढ़ती नजर आई।

इंफाल घाटी के जिलों में स्थिति सबसे अधिक प्रभावित रही, जहां बिष्णुपुर जिले के त्रोंगलाओबी में सात अप्रैल को हुए बम हमले के विरोध में जॉइंट एक्शन कमेटी (जेएसी) ने पांच दिवसीय बंद का आह्वान किया है। इस हमले में दो मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत ने लोगों को झकझोर कर रख दिया था, जिसके बाद से ही आक्रोश धीरे-धीरे उभर रहा था। बंद के दौरान इंफाल पश्चिम के सगोलबंद और पटसोई जैसे इलाकों में प्रदर्शनकारियों ने सड़कों को जाम कर दिया, जिससे यातायात पूरी तरह ठप हो गया। सार्वजनिक परिवहन सेवाएं बंद रहीं और निजी वाहन भी सड़कों पर नजर नहीं आए। हालात इतने गंभीर हो गए कि कई जगहों पर आपात सेवाओं को भी प्रभावित होना पड़ा।

दूसरी ओर, राज्य के पहाड़ी इलाकों में भी स्थिति कम तनावपूर्ण नहीं है। यूनाइटेड नागा काउंसिल द्वारा बुलाए गए तीन दिवसीय बंद का असर नागा बहुल जिलों में साफ दिखाई दे रहा है। यह बंद उखरुल जिले में 18 अप्रैल को दो तंगखुल नागा व्यक्तियों की हत्या के विरोध में बुलाया गया है। इस घटना ने पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों के बीच गहरा आक्रोश पैदा कर दिया है। नोनी जिले और इंफाल पूर्व के याइंगांगपोकपी जैसे इलाकों में बंद समर्थकों ने सड़क मार्ग पूरी तरह अवरुद्ध कर दिया, जिससे न केवल आम लोगों की आवाजाही बाधित हुई, बल्कि केंद्रीय सुरक्षा बलों के संचालन में भी मुश्किलें खड़ी हो गईं।

राज्य में लगातार हो रही ऐसी घटनाओं ने पहले से ही नाजुक सामाजिक संतुलन को और कमजोर कर दिया है। विभिन्न समुदायों के बीच अविश्वास और तनाव बढ़ता जा रहा है, जिससे शांति बहाली की कोशिशें भी प्रभावित हो रही हैं। प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हालात अभी भी चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। कई संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। इस बीच, बंद के कारण आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दैनिक जरूरतों की वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित हो रही है और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच भी कठिन हो गई है। स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तर बंद रहने से शैक्षणिक और प्रशासनिक गतिविधियां भी बाधित हो रही हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे लगातार भय और अनिश्चितता के माहौल में जीने को मजबूर हैं, जहां हर दिन नई चिंता लेकर आता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि मणिपुर में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए केवल सुरक्षा उपाय पर्याप्त नहीं होंगे, बल्कि विभिन्न समुदायों के बीच संवाद और विश्वास बहाली की आवश्यकता है। जब तक सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर समाधान नहीं निकाला जाता, तब तक इस तरह के विरोध और बंद राज्य के सामान्य जीवन को प्रभावित करते रहेंगे।

फिलहाल, मणिपुर एक बार फिर ऐसे मोड़ पर खड़ा है, जहां हालात को संभालना प्रशासन और समाज दोनों के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। आने वाले दिनों में स्थिति किस दिशा में जाएगी, यह काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकार और संबंधित संगठन किस प्रकार मिलकर इस संकट का समाधान निकालते हैं।

करीब दो दशक पुराने मालेगांव धमाके केस में बड़ा फैसला: सभी आरोपी बरी, उठे नए सवाल

मुंबई/मालेगांव। महाराष्ट्र के बहुचर्चित मालेगांव बम धमाका 2006 मामले में एक बड़ा और अहम मोड़ सामने आया है, जहां बॉम्बे हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा गिरफ्तार चारों आरोपियों—लोकेश शर्मा, धन सिंह, राजेंद्र चौधरी और मनोहर नरवरिया—को सभी आरोपों से बाइज्जत बरी कर दिया है। अदालत ने चार्ज फ्रेमिंग को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह पाया कि आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त और ठोस साक्ष्य मौजूद नहीं हैं, जिनके आधार पर मुकदमा चलाया जा सके। इस फैसले के साथ ही करीब 20 साल पुराने इस मामले में एक महत्वपूर्ण कानूनी पड़ाव पूरा हो गया है, लेकिन साथ ही कई नए सवाल भी खड़े हो गए हैं।

यह मामला 8 सितंबर 2006 को मालेगांव में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों से जुड़ा है, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। शब-ए-बारात के मौके पर बड़ा कब्रिस्तान, हमीदिया मस्जिद और मुशावरत चौक जैसे प्रमुख स्थानों पर हुए धमाकों में 37 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 200 से अधिक लोग घायल हुए थे। घटना के बाद शुरुआती जांच महाराष्ट्र एटीएस को सौंपी गई, जिसने इसे प्रतिबंधित संगठन सिमी से जोड़ते हुए 9 मुस्लिम युवकों को गिरफ्तार किया। 2006 से 2011 तक एटीएस की जांच इसी दिशा में आगे बढ़ती रही और 2011 में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने भी इस थ्योरी का समर्थन किया।

हालांकि, इस केस में बड़ा मोड़ तब आया जब 2010 में स्वामी असीमानंद के बयान ने पूरे घटनाक्रम को नई दिशा दे दी। उन्होंने मालेगांव और अन्य धमाकों में हिंदू संगठनों की संलिप्तता का दावा किया, जिससे पहले की जांच पर सवाल खड़े होने लगे। इसके बाद 2011 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने जांच अपने हाथ में ली और एटीएस तथा सीबीआई की थ्योरी को खारिज करते हुए केस की दिशा बदल दी। एनआईए ने 2013 में चार नए आरोपियों को गिरफ्तार किया और कहा कि पहले गिरफ्तार किए गए 9 मुस्लिम आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं हैं।

एनआईए की इसी रिपोर्ट के आधार पर 2021 में उन सभी 9 आरोपियों को बरी कर दिया गया, जिन पर वर्षों तक आतंकवाद के आरोप लगे रहे। इस दौरान यह भी स्पष्ट हुआ कि एटीएस और एनआईए की जांच में काफी विरोधाभास थे, जिससे पूरे मामले की विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगे। बाद में 2019 में एनआईए द्वारा गिरफ्तार चारों आरोपियों को जमानत मिल गई थी, और अब हाई कोर्ट के ताजा फैसले ने चार्ज फ्रेमिंग को ही खारिज कर उन्हें पूरी तरह निर्दोष घोषित कर दिया है।

इस पूरे घटनाक्रम ने एक गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर मालेगांव धमाकों का असली दोषी कौन है। जब पहले गिरफ्तार किए गए आरोपी भी बरी हो चुके हैं और बाद में गिरफ्तार किए गए आरोपियों पर भी आरोप साबित नहीं हो पाए, तो यह मामला एक अनिश्चित स्थिति में पहुंच गया है। करीब दो दशकों तक चली जांच, बदलती थ्योरी और अलग-अलग एजेंसियों के विरोधाभासी निष्कर्षों ने न्यायिक प्रक्रिया पर भी बहस छेड़ दी है।

मामले में राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और भाजपा नेता गिरीश महाजन ने इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अब सच्चाई सामने आ चुकी है और यह स्पष्ट हो गया है कि निर्दोष लोगों को फंसाया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले को राजनीतिक रंग दिया गया और जांच को भटकाया गया। उनके बयान से यह संकेत मिलता है कि आने वाले समय में इस मुद्दे पर राजनीतिक बहस और तेज हो सकती है।

इस केस में पहले गिरफ्तार किए गए आरोपियों में नूर-उल-हुदा, शब्बीर अहमद, रईस अहमद, सलमान फारसी, फारोग मगदूमी, शेख मोहम्मद अली, आसिफ खान, मोहम्मद जाहिद और अबरार अहमद शामिल थे, जिनमें से एक की मृत्यु हो चुकी है, जबकि बाकी सभी अदालत से बरी हो चुके हैं। लंबे समय तक जेल में रहने के बाद उनकी रिहाई ने भी न्याय प्रणाली और जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं।

कुल मिलाकर, मालेगांव बम धमाका मामला अब एक ऐसे मोड़ पर आ गया है, जहां कानूनी प्रक्रिया तो एक चरण में पूरी हो चुकी है, लेकिन सच्चाई अब भी अधूरी प्रतीत होती है। यह मामला न केवल एक आतंकी घटना का प्रतिनिधित्व करता है, बल्कि यह जांच एजेंसियों की जवाबदेही, न्यायिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता और राजनीतिक हस्तक्षेप जैसे मुद्दों को भी उजागर करता है। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या इस मामले में कोई नई जांच या पहल होती है, या फिर यह केस इसी तरह अनुत्तरित सवालों के साथ इतिहास का हिस्सा बन जाएगा।

संपादकीय

"ग्रामीण भारत के 30% स्कूलों में मैदान नहीं, कहीं झाड़ियाँ उगीं तो कहीं दबंगों का कब्ज़ा"

भारत की अधिकांश जनसंख्या गाँवों में बसती है, जहाँ की मिट्टी ने मिल्खा सिंह, पी.टी. उषा और नीरज चोपड़ा जैसे महान खिलाड़ी दिए हैं। इसके बावजूद, ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में खेलों की स्थिति अत्यंत दयनीय बनी हुई है। विभिन्न शिक्षा रिपोर्टों और सरकारी आंकड़ों (जैसे UDISE+) के अनुसार, आज भी लगभग 30 प्रतिशत से अधिक सरकारी स्कूलों के पास अपना स्वयं का खेल का मैदान नहीं है। जहाँ मैदान उपलब्ध भी हैं, वहाँ उनका रखरखाव इतना खराब है कि वे खेल गतिविधियों के लिए सुरक्षित नहीं माने जा सकते। बाउंड्री वॉल का न होना, मैदान में झाड़ियाँ उगना या स्थानीय लोगों द्वारा अतिक्रमण करना एक आम समस्या बन गई है, जिसके कारण बच्चों को सड़कों या संकरी गलियों में खेलने को मजबूर होना पड़ता है। संसाधनों की यह कमी केवल बुनियादी ढांचे तक सीमित नहीं है, बल्कि उपकरणों के स्तर पर भी काफी चिंताजनक है। बजट का अभाव ग्रामीण विद्यालयों के लिए सबसे बड़ी बाधा है। शिक्षा का अधिकांश बजट शिक्षकों के वेतन और मिड-डे मील जैसी अनिवार्य योजनाओं में ही समाप्त हो जाता है, जिससे खेलों के लिए नगण्य राशि बचती है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, एक बड़े प्रतिशत स्कूलों में खेल के नाम पर केवल एक फटी हुई फुटबॉल या कुछ पुराने क्रिकेट बैट ही होते हैं। बास्केटबॉल, वॉलीबॉल या एथलेटिक्स जैसे खेलों के लिए आवश्यक नेट, पोल और ट्रैक तो ग्रामीण भारत के अधिकांश विद्यालयों के लिए आज भी एक विलासिता जैसे हैं। इसके अतिरिक्त, शारीरिक शिक्षकों के रिक्त पद एक और गंभीर संकट हैं। देश के लगभग 50 प्रतिशत ग्रामीण माध्यमिक स्कूलों में प्रशिक्षित खेल प्रशिक्षक नहीं हैं, जिसके कारण बच्चों को खेलों की बारीकियों और नियमों की जानकारी नहीं मिल पाती। बिना सही मार्गदर्शन के, प्रतिभाशाली बच्चे भी जिला या राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं तक पहुँचने से पहले ही दम तोड़ देते हैं।

सामाजिक और नीतिगत स्तर पर भी ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को वह सहयोग नहीं मिल पाता जिसकी वे हकदार हैं। ग्रामीण परिवेश में आज भी 'पढ़ोगे-लिखोगे तो बनोगे नवाब' वाली कहावत हावी है, जहाँ खेलों को पढ़ाई में बाधा माना जाता है। केंद्र सरकार की 'खेलो इंडिया' जैसी योजनाएं निस्संदेह सराहनीय हैं, लेकिन इनका वास्तविक लाभ अभी भी शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों तक ही सिमटा हुआ है। ग्रामीण ब्लॉकों में इन योजनाओं का क्रियान्वयन बेहद सुस्त है। संसाधनों के इस अभाव का सीधा परिणाम ग्रामीण युवाओं के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। खेलों की अनुपलब्धता के कारण ग्रामीण बच्चे शारीरिक गतिविधियों से दूर होकर मोबाइल गेमिंग और डिजिटल व्यसनों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। यदि भारत को वास्तव में एक वैश्विक खेल महाशक्ति बनना है, तो हमें अपनी नीतियों के केंद्र में ग्रामीण विद्यालयों को रखना होगा। जब तक गाँव के हर स्कूल में एक समतल मैदान, आवश्यक खेल उपकरण और एक समर्पित कोच की व्यवस्था नहीं होगी, तब तक 'फिट इंडिया' और ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने का सपना अधूरा ही रहेगा। इसके लिए पंचायत स्तर पर बजटीय आवंटन बढ़ाना और निजी क्षेत्रों को खेल बुनियादी ढांचे में निवेश के लिए प्रोत्साहित करना अनिवार्य है।

मजबूत तूफान ले रहे भारत का इम्तिहान

"कहीं न कहीं हमारी नीति भटक गई है। बड़े टकरावों में शांति वार्ता स्थापना प्रक्रिया का हम हिस्सा नहीं हैं, लेकिन सनद रहे कि हमारे राजनीतिक दल पूरी तरह से विधानसभा चुनावों में व्यस्त हैं और उनके पास राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के लिए कोई समय नहीं है।

भारत एक और चुनावी दौर से गुजर रहा है। राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और मुद्दे राज्य और राष्ट्रीय, दोनों स्तरों के हैं। चुनावों के बीच ही, केंद्र सरकार ने जल्दबाजी में संसद में महिलाओं के लिए कोटा और संसदीय क्षेत्रों के परिसीमन पर विवादित बिल पास करवाने की कोशिश की। इन कोशिशों का नतीजा जो भी हो, लेकिन इनसे राष्ट्रीय मुद्दों से ध्यान भटक जाता है।

आज अंतर्राष्ट्रीय संकटों से हमारी अर्थव्यवस्था को खतरा बन रहा है। हमें गैस की कमी होने की आहट मिल रही है, जिससे रसायन, खाद, सिरेमिक, शीशा और वस्त्र उद्योग से लेकर आम रेस्तरां जैसे कामधंधे गहरे तक प्रभावित हो सकते हैं। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का असर हवाई किराये और इंडस्ट्रियल डीज़ल पर साफ़ दिखा है। देश सांस रोके हुए है कि चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल-डीज़ल की कीमतें कहां जाएंगी।

महंगाई अधिकांश घरेलू वस्तुओं को प्रभावित कर रही है, और आपूर्ति श्रृंखला में पड़े व्यवधान से प्रभावित हुई व्यवस्था में दुकानदार कीमतें बढ़ा रहे हैं। मध्य-पूर्व से बड़े पैमाने पर कारोबार करने वाले व्यापारिक घराने सरकार से राहत की गुहार लगा रहे हैं। खाद उत्पादन और आयात में बड़े पैमाने पर रुकावट बनने से खाद्य आत्मनिर्भरता खतरे में पड़ गई है।

खाड़ी देश अब वैश्विक खाद्य आर्थिकी का एक अभिन्न अंग हैं। लंदन यूनिवर्सिटी के 'सोअस' मिडिल ईस्ट इंस्टिट्यूट (स्कूल ऑफ़ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज़) के निदेशक एडम हनीह ने फाइनेंशियल टाइम्स में लिखा है—'खाड़ी मुल्क अब सीधे तौर पर खाद्य उत्पादन और वितरण श्रृंखला को स्वरूप देते हैं। वे आवश्यक रासायनिक घटकों के आपूर्तिदाता व बड़ी मात्रा में खाद निर्यातक हैं। जिन रास्तों से होकर मध्य पूर्व, केंद्रीय और पूर्वी एशिया के अधिकांश हिस्से की जरूरत का खाद्य एवं कृषि उत्पादन गुजरता है, उस पर उनका नियंत्रण है... खाड़ी क्षेत्र में युद्ध का आसन्न परिणाम अकाल और खाद्य असुरक्षा है। इस सच्चाई का वजन उस दुनिया पर भारी पड़ने वाला है जो लड़ाई के असर को तेल की कीमतों में अस्थिरता के संकीर्ण चश्मे से देख रही है।'

यह सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब उद्योग-धंधे पहले से ही अमेरिका द्वारा लगाए भारी टैरिफ के प्रभावों से उबरने में जूझ रहे हैं। मार्च माह में भारत को मिले कच्चे तेल की औसत खरीद कीमत 125 डॉलर थी, जो मध्य-पूर्व में लड़ाई की वजह से बीच-बीच में 150 डॉलर तक पहुंची थी। यदि युद्धविराम जारी रहे, तब भी कीमतें ऊंची बनी रहेंगी क्योंकि खाड़ी देशों के तेल उत्पादन-वितरण ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है।

इस परिदृश्य में महंगाई बढ़ना तय है, जब तक कि नई आपूर्ति लाइनें विकसित करने और कुछ पुरानी (रूसी) सप्लाई लाइनों को बहाल करने के वास्ते बड़े कदम नहीं उठाए जाते। जरूरत है युद्धस्तर पर राजनयिक संवाद पुनः स्थापित करने की, असफलता नुकसानदायक होगी। निस्संदेह, ऊर्जा कीमतों में बढ़ोतरी से ज़्यादातर दूसरी चीज़ों और सेवाओं की कीमतों में क्रमवार उछाल आना स्वाभाविक है, क्योंकि उत्पादन एवं परिवहन लागत पर काफी असर पड़ेगा। युद्ध के व्यवधानों से इकाइयां बंद हो रही हैं, जिससे बेरोज़गारी बढ़ रही है। इसका असर नोएडा में हाल ही में दिखा। जहां निराश कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे थे और हिंसक भी हो रहे हैं। इस स्थिति का इस्तेमाल दुश्मन ताकतें कर सकती हैं। इससे अर्थव्यवस्था को खतरा है; वहीं कूटनीतिक रूप से हम खुद को दलदल में फंसे पा रहे हैं। वर्ष 1999 का कारगिल युद्ध भारत ने निर्णायक तौर पर जीता और विदेशी घुसपैठिए सैनिकों को खदेड़ा था। उस वक्त भारत को सशक्त राजनयिक समर्थन हासिल हुआ। विदेशी नीति एवं कूटनीतिक संबंधों में एक साथ सफलता मिली। रेखांकित करना चाहूंगा—उस साल जून में कोलोन शिखर वार्ता के दौरान, जी-8 ने पाक द्वारा एलओसी उल्लंघन करने की आलोचना कर भारत का समर्थन किया। यूरोपियन यूनियन ने भी पाक की ताड़ना की और क्षेत्र में भाईचारा बनाए रखने की भारतीय कोशिशों को सराहा। चीन ने तटस्थता बनाए रख दोनों पक्षों से एलओसी का सम्मान करने को आग्रह किया।

तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने पाक के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया और कहा कि तुरंत बिना शर्त अपने सैनिकों को नियंत्रण रेखा से अपने इलाके में वापस बुलाए। पुराने सहयोगी रूस ने, कूटनीतिक रूप से और सैन्य साजो-सामान से हमारा साथ निभाया। भारत को व्यापक समर्थन मिला और पाक अलग-थलग पड़ गया। प्रतिबंधों से आतंकवाद का प्रायोजक बनने तक सिमट गया।

आज, वही दुनिया अलग है। जब अमेरिका ने ईरान के साथ वार्ता करनी चाही, तो उसने पाकिस्तान और उसके फील्ड मार्शल की मदद ली। ईरान भी पाकिस्तान की भूमिका पर सहमत हुआ और मध्यस्थता स्वीकारी। पाक जनरल को व्हाइट हाउस में विशेष निमंत्रण पर बुला शराब-लजीज़ भोजन परोसा। उच्च श्रेणी में स्थान दिया। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ पारस्परिक सुरक्षा और रक्षा समझौता किया है। पाक ने अक्तूबर, 2024 में शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन की मेजबानी की और चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा परियोजना के तहत बीआरआई के माध्यम से एक महत्वपूर्ण रणनीतिक धुरी बना हुआ है। वहीं इस्लामाबाद-तेहरान-इस्ताम्बुल रेललाइन को पुनः चालू किया जा रहा है। इससे पाकिस्तान के संबंध चीन, तुर्की और केंद्रीय एशिया के साथ और प्रगाढ़ होंगे। दूसरी तरफ, चाबहार बंदरगाह हमारे हाथ से जाता रहा, जो ईरान और मध्य एशिया तक पहुंच बनाने में हमारे लिए एक अहम कड़ी था। पाक बांग्लादेश के साथ राजनयिक संबंध पुनः स्थापित कर आर्थिक-रणनीतिक मोर्चे पर तेजी से बढ़ रहा है। पाक को सुरक्षा परिषद में भी अस्थाई सदस्यता मिली है।

आज, पश्चिमी मोर्चे पर हमारा सामना पाक से है, उत्तर और पूर्वी सीमा पर चीन से और पूर्व में ही बांग्लादेश से है। चीन, अरुणाचल प्रदेश सीमा पर अपना बुनियादी ढांचा स्थापित कर रहा है। हमारे इलाके की जगहों के नाम बदल अरुणाचल के साथ-साथ लद्दाख के बड़े इलाकों पर भी दावा ठोकता आ रहा है। सनद रहे कि चीन-पाक खुद को 'आयरन ब्रदर्स' कहते हैं। अपने बीच की करीबी को 'ऑल-वेदर पार्टनरशिप' बताते हैं।

मई, 2025 के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, चीन ने पाक को महत्वपूर्ण मदद पहुंचाई। क्या ऐसा इसलिए कि बदनाम-दिवालिया होने के बाद, पाकिस्तानियों ने विनम्रता अपनाई जबकि हमने अपनी बढ़ती अर्थव्यवस्था के गुमान में सौदबाजी करना चुना। हाल के सभी युद्धों और झगड़ों के दौरान, हमने चुप्पी साधे रखी (और इसे रणनीतिक चुप्पी बताया जा रहा है)। जॉन एफ कैनेडी ने सही कहा था—'हमें कभी भी डर के मारे बातचीत नहीं करनी चाहिए। लेकिन हमें बातचीत करने से कभी डरना भी नहीं चाहिए।'

कहीं न कहीं हमारी नीति भटक गई है। बड़े टकरावों में शांति वार्ता स्थापना प्रक्रिया का हम हिस्सा नहीं हैं, लेकिन सनद रहे कि हमारे राजनीतिक दल पूरी तरह से विधानसभा चुनावों में व्यस्त हैं और उनके पास राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के लिए कोई समय नहीं है। उम्मीद है यह तूफ़ान गुज़र जाएगा और हमें अपने अकेलेपन से जूझता छोड़कर।

प्रेरणा

महिला सशक्तिकरण के अग्रदूत: डॉ. भीमराव अंबेडकर की क्रांतिकारी दृष्टि

भारतीय समाज की ऐतिहासिक संरचना में महिलाओं की स्थिति लंबे समय तक सीमित, निर्भर और उपेक्षित रही है। सामाजिक परंपराओं और रूढ़ियों ने उन्हें ऐसे दायरे में बांध दिया था, जहां उनकी स्वतंत्रता, शिक्षा और अधिकारों का विस्तार संभव नहीं था। जब भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की, तब यह उम्मीद की गई थी कि समाज के हर वर्ग को समान अधिकार और अवसर मिलेंगे, लेकिन महिलाओं के संदर्भ में यह परिवर्तन तत्काल दिखाई नहीं दिया। ऐसे समय में भीमराव अंबेडकर ने एक सशक्त और दूरदर्शी नेतृत्व का परिचय देते हुए महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए ऐतिहासिक प्रयास किए।

डॉ. अंबेडकर ने यह समझ लिया था कि किसी भी समाज की वास्तविक प्रगति तब तक संभव नहीं है, जब तक वहां महिलाओं को बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता। उन्होंने महिलाओं की सामाजिक और कानूनी स्थिति का गहराई से अध्ययन किया और पाया कि वे संपत्ति के अधिकार से वंचित हैं, विवाह में उनकी भूमिका निर्णय लेने वाली नहीं, बल्कि केवल पालन करने वाली है, और शिक्षा के अवसर भी उनके लिए अत्यंत सीमित हैं। इस असमानता को समाप्त करने के लिए उन्होंने एक व्यापक और दूरगामी कानून की आवश्यकता महसूस की, जिसके परिणामस्वरूप 'हिंदू कोड बिल' का निर्माण हुआ।

यह बिल उस समय के लिए एक क्रांतिकारी पहल थी, जिसमें महिलाओं को कई महत्वपूर्ण अधिकार देने का प्रस्ताव रखा गया था। इसमें बेटियों को पिता की संपत्ति में समान हिस्सेदारी देने की बात कही गई, जिससे वे आर्थिक रूप से सशक्त हो सकें। इसके अलावा, महिलाओं को तलाक का अधिकार देने का प्रस्ताव भी इस बिल का हिस्सा था, जो उन्हें असमान और अन्यायपूर्ण विवाह से मुक्त होने का अवसर देता। बहुविवाह जैसी प्रथाओं को समाप्त कर एक पत्नी प्रथा लागू करने का विचार भी इसमें शामिल था, जिससे महिलाओं के सम्मान और गरिमा की रक्षा हो सके। डॉ. अंबेडकर का यह प्रयास केवल कानूनी सुधार नहीं था, बल्कि यह सामाजिक चेतना को बदलने का एक सशक्त माध्यम भी था।

जब इस बिल को संसद में प्रस्तुत किया गया, तो इसका विरोध भी उतना ही तीव्र हुआ। समाज के कई कट्टरपंथी वर्गों ने इसे भारतीय संस्कृति और परंपराओं के खिलाफ बताया। उनका मानना था कि इस प्रकार के बदलाव से परिवार व्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और समाज में अस्थिरता उत्पन्न होगी। लेकिन डॉ. अंबेडकर ने इन सभी विरोधों का दृढ़ता से सामना किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि परंपराएं तभी तक उचित हैं, जब तक वे न्याय और समानता के सिद्धांतों के अनुरूप हों। यदि कोई परंपरा किसी वर्ग के साथ भेदभाव करती है, तो उसे बदलना आवश्यक है।

डॉ. अंबेडकर ने लगभग चार वर्षों तक इस बिल को पारित कराने के लिए अथक प्रयास किए। उन्होंने संसद में अपने तर्कों और विचारों के माध्यम से यह समझाने की कोशिश की कि यह बिल केवल महिलाओं के हित में नहीं, बल्कि पूरे समाज के विकास के लिए आवश्यक है। लेकिन बार-बार इस बिल को टाल दिया गया और इसे लागू करने में गंभीरता नहीं दिखाई गई। यह स्थिति उनके लिए अत्यंत निराशाजनक थी, क्योंकि वे इसे एक सामाजिक क्रांति का आधार मानते थे।

अंततः, जब उन्हें यह महसूस हुआ कि उनके प्रयासों को नजरअंदाज किया जा रहा है और सरकार इस मुद्दे पर गंभीर नहीं है, तो उन्होंने एक साहसिक और ऐतिहासिक निर्णय लिया। वर्ष 1951 में उन्होंने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। उनका यह कदम यह दर्शाता है कि वे अपने सिद्धांतों और मूल्यों के प्रति कितने प्रतिबद्ध थे। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि महिलाओं के अधिकारों से समझौता करना उनके लिए संभव नहीं है, चाहे इसके लिए उन्हें अपने पद का त्याग ही क्यों न करना पड़े।

हालांकि उस समय हिंदू कोड बिल पारित नहीं हो पाया, लेकिन डॉ. अंबेडकर के प्रयास व्यर्थ नहीं गए। उनके विचारों और सिद्धांतों ने समाज में एक नई सोच को जन्म दिया। बाद में इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम और हिंदू विवाह अधिनियम जैसे महत्वपूर्ण कानून बनाए गए, जिन्होंने महिलाओं को संपत्ति में अधिकार, विवाह में समानता और कानूनी सुरक्षा प्रदान की। इन कानूनों के माध्यम से महिलाओं की स्थिति में धीरे-धीरे सुधार हुआ और उन्हें समाज में एक सम्मानजनक स्थान प्राप्त हुआ।

डॉ. अंबेडकर का यह योगदान केवल कानून बनाने तक सीमित नहीं था, बल्कि यह एक व्यापक सामाजिक परिवर्तन की शुरुआत थी। उन्होंने यह सिद्ध किया कि महिलाओं को सशक्त बनाए बिना समाज का समग्र विकास संभव नहीं है। उनका यह दृष्टिकोण आज भी उतना ही प्रासंगिक है, जितना उस समय था। उन्होंने समाज को यह संदेश दिया कि समानता और न्याय केवल आदर्श नहीं, बल्कि एक आवश्यक वास्तविकता होनी चाहिए।

आज के समय में महिलाएं शिक्षा, राजनीति, विज्ञान, खेल और व्यापार जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर रही हैं। वे आत्मनिर्भर बन रही हैं और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक भी हैं। यह परिवर्तन अचानक नहीं हुआ है, बल्कि इसके पीछे डॉ. अंबेडकर जैसे महान नेताओं के संघर्ष और दूरदर्शिता का परिणाम है। उनके प्रयासों ने समाज में एक ऐसी नींव रखी, जिस पर आज का आधुनिक और प्रगतिशील भारत खड़ा है।

फिर भी, यह कहना उचित होगा कि महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। आज भी कई क्षेत्रों में उन्हें भेदभाव, हिंसा और असमानता का सामना करना पड़ता है। ऐसे में डॉ. अंबेडकर के विचार हमें प्रेरणा देते हैं कि हम इस संघर्ष को जारी रखें और एक ऐसा समाज बनाएं, जहां हर व्यक्ति को समान अवसर और सम्मान मिले।

डॉ. अंबेडकर का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चे परिवर्तन के लिए केवल विचार ही नहीं, बल्कि साहसिक निर्णय और दृढ़ संकल्प भी आवश्यक होते हैं। उन्होंने अपने जीवन में अनेक चुनौतियों का सामना किया, लेकिन कभी अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटे। महिलाओं के अधिकारों के लिए उनका संघर्ष भारतीय समाज के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जो हमेशा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा।

पश्चिम बंगाल में सत्ता विरोधी लहर का फायदा क्या उठा पाएगी भाजपा?

पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। सवाल सीधा है कि क्या सत्ताविरोधी माहौल को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अपने पक्ष में मोड़ पाएगी? या फिर ममता बनर्जी का जादू एक बार फिर कायम रहेगा? वैसे राज्य में चुनावी हवा भले ही बदलाव की सुगबुगाहट दिखा रही हो, लेकिन जमीन पर हालात इतने सरल नहीं हैं। देखा जाये तो इस बार के चुनावों में भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार रैलियां, केंद्रीय नेतृत्व की सक्रियता और संगठन की आक्रामक रणनीति यह संकेत देती है कि पार्टी किसी भी कीमत पर बंगाल में सत्ता का स्वाद चखना चाहती है। दूसरी ओर, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) भी अपनी पकड़ ढीली पड़ने देने के मूड में नहीं है। ममता बनर्जी, जो लंबे समय से राज्य की राजनीति का केंद्र रही हैं, अब भी अपने जनाधार और कल्याणकारी योजनाओं के भरोसे मैदान में डटी हुई हैं। उधर, भाजपा के लिए उम्मीद की सबसे बड़ी वजह है 'एंटी-इंकम्बेंसी' यानी सत्ता के खिलाफ बढ़ती नाराज़गी। टीएमसी सरकार पर भ्रष्टाचार, प्रशासनिक अक्षमता और कानून-व्यवस्था के सवालों को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर रहा है। भर्ती घोटाले, स्थानीय स्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं की दबंगई और राजनीतिक हिंसा जैसे मुद्दे भाजपा के चुनावी एजेंडे के केंद्र में हैं। पार्टी का दावा है कि जनता बदलाव चाहती है और इस बार वोट उसी दिशा में जाएगा।

लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी उतना ही मजबूत है। ममता बनर्जी ने बीते वर्षों में महिला मतदाताओं, ग्रामीण गरीबों और अल्पसंख्यकों के बीच अपनी पकड़ मजबूत की है। 'लक्ष्मी भंडार' जैसी योजनाओं ने महिलाओं के बीच भरोसा पैदा किया है, जबकि अन्य सामाजिक योजनाओं ने गरीब तबकों को सीधे लाभ पहुंचाया है। यही कारण है कि भाजपा के आक्रामक अभियान के बावजूद टीएमसी का आधार पूरी तरह हिलता नजर नहीं आता।

इसके अलावा, भाजपा की रणनीति में एक अहम किरदार हैं शुभेन्दु अधिकारी, जो कभी ममता बनर्जी के करीबी सहयोगी थे और अब उनके सबसे बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी बन चुके हैं। शुभेन्दु अधिकारी ने नंदीग्राम में ममता बनर्जी को मात दी थी और इस बार ममता बनर्जी को उनके गढ़ भवानीपुर में चुनौती दे रहे हैं। शुभेन्दु अधिकारी राज्य में भाजपा का चेहरा बनने का प्रयास कर रहे हैं हालांकि, उनका प्रभाव सीमित इलाकों तक ही केंद्रित माना जाता है, और पूरे बंगाल में एक व्यापक लहर खड़ी करना उनके लिए आसान नहीं है।

हम आपको याद दिला दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव भाजपा के लिए पश्चिम बंगाल में टर्निंग प्वाइंट साबित हुए थे। पार्टी ने उस चुनाव में अप्रत्याशित सफलता हासिल करते हुए खुद को एक मजबूत विपक्ष के रूप में स्थापित किया था। उसी प्रदर्शन के आधार पर भाजपा को उम्मीद थी कि वह विधानसभा चुनाव में सत्ता तक पहुंच सकती है। लेकिन बाद के चुनावी अनुभवों ने यह भी दिखाया कि लोकसभा और विधानसभा की राजनीति में मतदाताओं का व्यवहार अलग हो सकता है।

एक और चुनौती भाजपा के सामने सांस्कृतिक और भाषाई असंतुलन की है। बंगाल की अपनी विशिष्ट पहचान है, और यहां बाहरी बनाम स्थानीय का मुद्दा अक्सर उभरता रहता है। भाजपा के कई नेताओं के बयान और रणनीतियां कभी-कभी स्थानीय संवेदनशीलताओं से मेल नहीं खातीं, जिससे पार्टी को नुकसान उठाना पड़ता है। टीएमसी इस मुद्दे को भुनाने में माहिर रही है और खुद को 'बंगाल की असली आवाज' के रूप में पेश करती है।

इसके अलावा, मतदाताओं के एक हिस्से में यह धारणा भी है कि भाजपा की राजनीति अत्यधिक ध्रुवीकरण पर आधारित है। धार्मिक और पहचान की राजनीति का असर भले कुछ क्षेत्रों में दिखता हो, लेकिन पूरे राज्य में यह रणनीति कितनी कारगर होगी, इस पर सवाल बना हुआ है। बंगाल का सामाजिक ताना-बाना जटिल है, और यहां की राजनीति सिर्फ एक मुद्दे पर नहीं टिकती। दूसरी ओर, टीएमसी के खिलाफ असंतोष को पूरी तरह नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। ग्रामीण इलाकों में विकास की असमानता, स्थानीय स्तर पर भ्रष्टाचार और रोजगार के अवसरों की कमी जैसे मुद्दे लोगों के बीच चर्चा में हैं। भाजपा इन्हीं सवालों को उठाकर खुद को एक वैकल्पिक शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहती है।

वैसे बंगाल की चुनावी लड़ाई सिर्फ आंकड़ों और नारों की नहीं है, बल्कि भावनाओं, पहचान और भरोसे की भी है। भाजपा के पास आक्रामक अभियान और राष्ट्रीय नेतृत्व का समर्थन है, लेकिन टीएमसी के पास जमीनी नेटवर्क और ममता बनर्जी की व्यक्तिगत लोकप्रियता है। इसलिए, यह कहना जल्दबाजी होगी कि सत्ताविरोधी लहर किसके पक्ष में जाएगी। भाजपा के लिए यह अवसर भी है और चुनौती भी क्योंकि उसे नाराज़गी को वोट में बदलना होगा। वहीं ममता बनर्जी के लिए यह अपनी विश्वसनीयता और जनसंपर्क की सबसे बड़ी परीक्षा है।

बहरहाल, इस चुनाव का नतीजा सिर्फ सत्ता परिवर्तन या सत्ता में पुनरावृत्ति तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह तय करेगा कि बंगाल की राजनीति आने वाले वर्षों में किस दिशा में आगे बढ़ेगी। फिलहाल, मैदान सजा है, दांव बड़े हैं और फैसला पूरी तरह जनता के हाथ में है, जो इस बार सिर्फ सरकार नहीं, बल्कि राजनीतिक कथा का अगला अध्याय लिखने जा रही है।

अभियान

अद्वैत की ज्योति से आलोकित भारत: आद्यगुरु शंकराचार्य का जीवन और उनका शाश्वत संदेश

भारतीय आध्यात्मिक परंपरा का इतिहास जब भी लिखा जाता है, तो उसमें कुछ ऐसे दिव्य व्यक्तित्वों का उल्लेख अवश्य होता है, जिन्होंने न केवल धर्म और दर्शन को नई दिशा दी, बल्कि समाज को एकता और समरसता का मार्ग भी दिखाया। ऐसे ही महान आचार्य थे आदि शंकराचार्य, जिन्हें अद्वैत वेदांत का प्रवर्तक, सनातन संस्कृति का पुनर्जागरणकर्ता और राष्ट्रीय एकता का सशक्त प्रतीक माना जाता है। उनका जीवन केवल एक साधु का जीवन नहीं था, बल्कि वह एक ऐसे चिंतक, दार्शनिक और राष्ट्रद्रष्टा का जीवन था, जिसने पूरे भारत को एक आध्यात्मिक सूत्र में पिरोने का प्रयास किया।

केरल के कालड़ी नामक छोटे से गांव में जन्मे शंकराचार्य बचपन से ही असाधारण प्रतिभा के धनी थे। उनके पिता शिवगुरु और माता आर्याम्बा अत्यंत धार्मिक और विद्वान थे, जिनके संस्कारों ने बालक शंकर के व्यक्तित्व को प्रारंभ से ही गढ़ना शुरू कर दिया था। कहा जाता है कि उन्होंने बहुत छोटी आयु में ही वेदों का अध्ययन कर लिया था और संस्कृत भाषा पर उनका अद्भुत अधिकार था। उनकी स्मरण शक्ति और तर्क क्षमता इतनी प्रखर थी कि विद्वान लोग भी उनकी प्रतिभा को देखकर चकित रह जाते थे।

बाल्यावस्था में ही उनके भीतर आध्यात्मिक जिज्ञासा प्रबल हो गई थी। वे केवल शास्त्रों का अध्ययन ही नहीं करते थे, बल्कि उनके गूढ़ अर्थों को समझने का भी प्रयास करते थे। उनकी माता ने उन्हें वेद, उपनिषद और पुराणों की शिक्षा दी, जिससे उनके भीतर धर्म के प्रति गहरी आस्था और ज्ञान की पिपासा उत्पन्न हुई। यही कारण था कि उन्होंने बहुत कम आयु में ही यह निर्णय ले लिया कि उनका जीवन सांसारिक सुखों के लिए नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और ब्रह्म की प्राप्ति के लिए समर्पित होगा।

उनके जीवन की एक अत्यंत प्रसिद्ध घटना उनके संन्यास से जुड़ी हुई है। जब उन्होंने संन्यास लेने की इच्छा व्यक्त की, तो उनकी माता इसके लिए तैयार नहीं हुईं। किंतु उनकी इच्छा इतनी प्रबल थी कि एक दिन पेरियार नदी के किनारे घटी एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। कहा जाता है कि जब एक मगरमच्छ ने उनके पैर को पकड़ लिया, तब उन्होंने अपनी माता से संन्यास की अनुमति मांगी और जैसे ही अनुमति मिली, मगरमच्छ ने उन्हें छोड़ दिया। यह घटना केवल एक कथा नहीं, बल्कि उनके संकल्प और ईश्वरीय इच्छा का प्रतीक मानी जाती है। अंततः उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और अपने जीवन को धर्म और दर्शन के प्रचार के लिए समर्पित कर दिया। संन्यास ग्रहण करने के बाद शंकराचार्य ने पूरे भारत का व्यापक भ्रमण किया। उस समय भारत अनेक धार्मिक मतों और संप्रदायों में विभाजित था, जिससे समाज में भ्रम और अस्थिरता उत्पन्न हो गई थी। उन्होंने अपने अद्वैत वेदांत के माध्यम से यह संदेश दिया कि समस्त सृष्टि एक ही परम सत्य, अर्थात ब्रह्म, का विस्तार है। उन्होंने 'ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या' का सिद्धांत प्रस्तुत करते हुए यह बताया कि यह संसार माया का रूप है और वास्तविक सत्य केवल ब्रह्म है।

उनका अद्वैत दर्शन केवल दार्शनिक विचार नहीं था, बल्कि यह जीवन जीने की एक संपूर्ण पद्धति थी। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है और यह भेद केवल अज्ञान के कारण प्रतीत होता है। जब मनुष्य ज्ञान प्राप्त करता है, तो वह इस भेद को समाप्त कर देता है और ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाता है। यह विचार उस समय के लिए अत्यंत क्रांतिकारी था, क्योंकि इससे सामाजिक भेदभाव और ऊंच-नीच की धारणाओं को चुनौती मिलती थी।

शंकराचार्य ने अपने विचारों को केवल शब्दों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्हें व्यवहार में भी उतारा। उन्होंने देश के चारों कोनों में चार प्रमुख मठों की स्थापना की, जिनका उद्देश्य धर्म और संस्कृति का संरक्षण करना और समाज को एकजुट करना था। उत्तर में बद्रिकाश्रम, दक्षिण में श्रृंगेरी, पश्चिम में द्वारका और पूर्व में पुरी स्थित गोवर्धन पीठ आज भी उनके द्वारा स्थापित परंपरा के प्रतीक हैं। इन मठों के माध्यम से उन्होंने न केवल आध्यात्मिक शिक्षा का प्रसार किया, बल्कि राष्ट्रीय एकता की भावना को भी सुदृढ़ किया।

उनकी रचनाएं भी उनके अद्वितीय ज्ञान और प्रतिभा का प्रमाण हैं। उन्होंने उपनिषद, भगवद्गीता और ब्रह्मसूत्र पर जो भाष्य लिखे, वे आज भी वेदांत दर्शन के आधार स्तंभ माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने अनेक स्तोत्रों की रचना की, जिनमें भक्ति और ज्ञान का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। उनकी भाषा सरल और प्रभावशाली थी, जिससे सामान्य व्यक्ति भी उनके विचारों को आसानी से समझ सकता था।

आद्यगुरु शंकराचार्य का जीवन अत्यंत अल्पकालिक था, लेकिन उनके कार्य इतने व्यापक और प्रभावशाली थे कि उन्होंने भारतीय इतिहास में अमिट छाप छोड़ी। मात्र 32 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने जीवन का ध्येय पूर्ण कर लिया और ब्रह्म में लीन हो गए। उनका यह जीवन हमें यह सिखाता है कि जीवन की महानता उसकी लंबाई में नहीं, बल्कि उसके उद्देश्य और कर्म में होती है।

आज के समय में जब समाज में विभाजन, भौतिकवाद और असहिष्णुता बढ़ रही है, तब शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन हमें एक नई दिशा प्रदान करता है। उनका संदेश हमें यह सिखाता है कि हम सभी एक ही परम सत्य के अंश हैं और हमें आपसी भेदभाव को छोड़कर एकता और समरसता की ओर बढ़ना चाहिए।

उनका जीवन और उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, जितने उस समय थे। वे केवल एक धार्मिक गुरु नहीं थे, बल्कि एक ऐसे विचारक थे, जिन्होंने समाज को एक नई दृष्टि दी। उनका योगदान केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण मानवता के लिए एक अमूल्य धरोहर है। आद्यगुरु शंकराचार्य का जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि हम अपने भीतर ज्ञान, सत्य और करुणा की ज्योति को प्रज्वलित करें और समाज में एकता और प्रेम का संदेश फैलाएं। उनके द्वारा दिखाया गया मार्ग आज भी हमें यह सिखाता है कि सच्चा धर्म वही है, जो हमें अपने भीतर के सत्य से जोड़ता है और समस्त संसार को एक परिवार के रूप में देखने की दृष्टि प्रदान करता है।

RNI No. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

पहलगाम की वह दर्दनाक शाम: एक साल बाद भी नहीं थमा मातम, यतीशभाई परमार के परिवार का जख्म आज भी हरा

भावनगर/श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के खूबसूरत पर्यटन स्थल पहलगाम में घटी वह भयावह घटना आज भी लोगों की यादों में ताजा है। एक साल पहले की वही तारीख, वही शाम और वही अचानक गूंजती गोलियों की आवाज—जिसने कई मासूम जिंदगियों को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। इस आतंकी हमले में गुजरात के भावनगर निवासी यतीशभाई परमार और उनके बेटे स्मित परमार की मौत ने एक पूरे परिवार को उजाड़ दिया था। समय बीतने के साथ जख्म भर जाते हैं, लेकिन इस परिवार के लिए वक्त जैसे वहीं थम गया है। एक साल बाद भी उनके घर में मातम का माहौल है और उस दिन की यादें आज भी उन्हें अंदर तक झकझोर देती हैं।

16 अप्रैल 2025 को यतीशभाई अपने परिवार के साथ धार्मिक यात्रा पर निकले थे। उनका उद्देश्य मोरारी बापू की कथा में शामिल होना था, जो श्रीनगर में आयोजित की जा रही थी। भावनगर से सुरेंद्रनगर होते हुए जम्मू तवी ट्रेन से पूरा परिवार जम्मू-कश्मीर पहुंचा था। धार्मिक आस्था और परिवार के साथ बिताए कुछ सुकून भरे पल, यही इस यात्रा का मकसद था। कथा में भाग लेने के बाद परिवार ने श्रीनगर से करीब 100 किलोमीटर दूर स्थित पहलगाम जाने का फैसला किया, जहां वे प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेना चाहते थे। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह यात्रा उनके जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी में बदल जाएगी।

उस दिन पहलगाम में पर्यटक सामान्य तरीके से घूम रहे थे। यतीशभाई और उनका बेटा स्मित भी साइड सीन का आनंद ले रहे थे। तभी अचानक गोलियों की आवाज गूंजने लगी। आतंकवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिससे वहां मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई। हर तरफ चीख-पुकार और अफरा-तफरी का माहौल बन गया। इसी दौरान यतीशभाई और उनके बेटे स्मित आतंकियों की गोली का शिकार हो गए। देखते ही देखते एक पिता और बेटे की जिंदगी वहीं खत्म हो गई। परिवार के साथ मौजूद काजलबेन परमार किसी तरह बच गईं, लेकिन उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने पति और बेटे को खो दिया—एक ऐसा मंजर जिसे भूल पाना किसी के लिए भी संभव नहीं।

इस हमले में अन्य लोग भी घायल हुए, जिनमें भावनगर के विनोदभाई डाभी भी शामिल थे, जिनके हाथ में गोली लगी थी। लेकिन यतीशभाई और उनके बेटे की मौत ने पूरे इलाके को शोक में डुबो दिया। यतीशभाई भावनगर में होटल व्यवसाय और सैलून के काम से जुड़े थे और अपने परिवार के लिए एक मजबूत सहारा थे। उनके जाने के बाद परिवार की दुनिया पूरी तरह बदल गई।

आज जब इस दर्दनाक घटना को एक साल पूरा हो चुका है, तब भी उनके परिवार की स्थिति सामान्य नहीं हो पाई है। यतीशभाई की पत्नी काजलबेन परमार इस सदमे से उबर नहीं पाई हैं। बताया जा रहा है कि वे गहरे मानसिक तनाव और अवसाद से गुजर रही हैं और हाल ही में उनकी हालत बिगड़ने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। उनके परिजनों का कहना है कि काजलबेन आज भी उस दिन को याद कर हर रोज रोती हैं और अपने पति और बेटे की यादों में खो जाती हैं। उनके लिए यह एक साल जैसे सदियों के बराबर रहा है।

परिवार के एक सदस्य ने बताया कि वे खुद उस घटना के प्रत्यक्षदर्शी थे और उन्होंने अपनी आंखों के सामने यह भयावह मंजर देखा। उन्होंने कहा कि यह घटना इतनी दर्दनाक थी कि आज भी उसे याद करते ही आंखों से आंसू निकल आते हैं। उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से सहायता जरूर मिली है, लेकिन किसी भी तरह की मदद उस खालीपन को नहीं भर सकती जो एक पिता और बेटे के जाने से पैदा हुआ है।

पड़ोसियों का भी कहना है कि पिछले एक साल से इस परिवार के घर में खुशी का माहौल नहीं लौटा है। हर दिन कोई न कोई उस घटना को याद करके रो पड़ता है। पड़ोसी भार्गवभाई भट्ट ने बताया कि काजलबेन की हालत बेहद चिंताजनक है और वे मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुकी हैं। उन्होंने कहा कि यह घटना इतनी भयावह थी कि कोई भी इसे भूल नहीं सकता और न ही ऐसा दर्द कभी पूरी तरह खत्म हो सकता है।

यह घटना न केवल एक परिवार के लिए, बल्कि पूरे समाज के लिए एक गहरा जख्म बन गई है। यह हमें याद दिलाती है कि आतंकवाद किस तरह निर्दोष लोगों की जिंदगी को पलभर में तबाह कर देता है। पहलगाम की वह काली शाम आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है और हर बार उसकी याद एक नई पीड़ा लेकर आती है।

एक साल बाद भी यतीशभाई और उनके बेटे की यादें उनके परिवार के साथ-साथ पूरे भावनगर में जिंदा हैं। उनकी कमी हर दिन महसूस की जाती है और उनकी याद में आंखें नम हो जाती हैं। यह कहानी केवल एक परिवार के दर्द की नहीं, बल्कि उन अनगिनत जिंदगियों की भी है, जो आतंकवाद की आग में झुलस जाती हैं और जिनका दर्द समय के साथ भी कम नहीं होता।

बुलेट ट्रेन परियोजना के अंतर्गत ब्लाक के कारण अहमदाबाद मंडल से चलने/गुजरने वाली ट्रेनें प्रभावित

पश्चिम रेलवे द्वारा यात्री सुविधाओं के उन्नयन तथा रेलवे अवसंरचना को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से, बुलेट ट्रेन परियोजना के अंतर्गत गेरतपुर–अहमदाबाद खंड पर चौथे प्रीकास्टेड पोर्टल बीम के लॉन्चिंग कार्य हेतु दिनांक 24 अप्रैल 2026 को ट्रैफिक ब्लॉक लिया जाएगा। इस महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग कार्य के कारण निम्नलिखित ट्रेन सेवाएं प्रभावित रहेंगी।

शॉर्ट टर्मिनेशन / ओरिजिनेशन ट्रेनें

ट्रेन संख्या 20902 गांधीनगर केपिटल–मुंबई सेंट्रल वंदे भारत एक्सप्रेस को दिनांक 24 अप्रैल 2026 को अहमदाबाद स्टेशन से प्रारंभ किया जाएगा तथा गांधीनगर केपिटल–अहमदाबाद के बीच निरस्त रहेगी।

ट्रेन संख्या 20901 मुंबई सेंट्रल–गांधीनगर केपिटल वंदे भारत एक्सप्रेस को दिनांक 24 अप्रैल 2026 को वटवा स्टेशन पर समाप्त (शॉर्ट टर्मिनेट) किया जाएगा तथा वटवा–गांधीनगर केपिटल के बीच निरस्त रहेगी।

पुनर्निर्धारण (Rescheduling)

ट्रेन संख्या 12009 मुंबई सेंट्रल–अहमदाबाद शताब्दी एक्सप्रेस दिनांक 24 अप्रैल 2026 को मुंबई सेंट्रल से 1 घंटा 15 मिनट विलंब से प्रस्थान करेगी।

निरस्त ट्रेनें (Cancelled Trains)

▸▸ ट्रेन संख्या 69102 वटवा–वडोदरा मेमू दिनांक 24 अप्रैल 2026 को निरस्त रहेगी।

▸▸ ट्रेन संख्या 69115 वडोदरा–वटवा मेमू दिनांक 24 अप्रैल 2026 को निरस्त रहेगी।

▸▸ ट्रेन संख्या 22959 वडोदरा–जामनगर इंटरसिटी दिनांक 23 अप्रैल 2026 को निरस्त रहेगी।

▸▸ ट्रेन संख्या 22960 जामनगर–वडोदरा इंटरसिटी दिनांक 24 अप्रैल 2026 को निरस्त रहेगी।

आंशिक निरस्त (Partial Cancellation)

ट्रेन संख्या 19033 वलसाड़–अहमदाबाद गुजरात क्वीन दिनांक 24 अप्रैल 2026 को वडोदरा–अहमदाबाद के बीच आंशिक रूप से निरस्त रहेगी।

विनियमन (Regulation of Trains)

ट्रेन संख्या 19484 आसनसोल–अहमदाबाद एक्सप्रेस दिनांक 24 अप्रैल 2026 को वडोदरा मंडल में 1 घंटा 40 मिनट रेगुलेट की जाएगी।

ट्रेन संख्या 12834 हावड़ा–अहमदाबाद एक्सप्रेस दिनांक 24 अप्रैल 2026 को वडोदरा मंडल में 1 घंटा 40 मिनट रेगुलेट की जाएगी।

ट्रेन संख्या 12755 काकीनाड़ा पोर्ट–भावनगर सुपरफास्ट एक्सप्रेस दिनांक 24 अप्रैल 2026 को वडोदरा मंडल में लगभग 45 मिनट रेगुलेट की जाएगी।

ट्रेन संख्या 12474 श्री माता वैष्णो देवी कटरा–गांधीधाम एक्सप्रेस दिनांक 24 अप्रैल 2026 को वडोदरा मंडल में 1 घंटा 45 मिनट रेगुलेट की जाएगी।

यात्रियों से अनुरोध है कि ट्रेनों के समय, ठहराव एवं अन्य अद्यतन जानकारी के लिए www.enquiry.indianrail.gov.in का अवलोकन करें।

कुंभलगढ़ का जंगल बना अग्निकुंड: चार दिनों से बेकाबू आग ने बढ़ाई चिंता, वन्यजीवों पर मंडराया संकट

पाली। राजस्थान के पाली जिले में स्थित कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य इन दिनों भीषण आग की चपेट में है, जिसने पूरे क्षेत्र को भय और अनिश्चितता के माहौल में डाल दिया है। पिछले चार दिनों से लगातार धधक रही यह आग अब तक काबू में नहीं आ सकी है और तेज हवाओं के कारण तेजी से फैलती जा रही है। नलवानिया बांध नाल और आसपास के पर्वतीय इलाकों से शुरू हुई आग ने देखते ही देखते विशाल वन क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया है, जिससे हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं।

दिन के समय आसमान में उठता घना धुआं और रात के अंधेरे में दूर-दूर तक दिखाई देती आग की लपटें इस आपदा की भयावहता को साफ बयां कर रही हैं। सादड़ी कस्बे की ऊंची इमारतों और आसपास के गांवों से लोग इस खौफनाक मंजर को देख रहे हैं, जहां जंगल जलता हुआ साफ नजर आ रहा है। आग की लपटें इतनी ऊंची उठ रही हैं कि कई किलोमीटर दूर से भी उनका दृश्य देखा जा सकता है। तेज हवाएं आग को और भड़का रही हैं, जिससे यह

लगातार नए इलाकों में फैलती जा रही है और नियंत्रण की कोशिशें और कठिन होती जा रही हैं।

वन विभाग और प्रशासन की टीमें लगातार मौके पर डटी हुई हैं और आग बुझाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियां और ऊबड़-खाबड़ पहाड़ी इलाकों के कारण राहत और बचाव कार्यों में काफी मुश्किलें आ रही हैं। कई स्थान ऐसे हैं जहां पहुंचना बेहद कठिन है, जिससे आग पर नियंत्रण पाने में देरी हो रही है। लगातार बदलती हवा की दिशा भी आग बुझाने के प्रयासों को प्रभावित कर रही है, जिससे स्थिति और जटिल बनती जा रही है। इस भीषण आग ने वन संपदा को भारी नुकसान पहुंचाया है। हजारों पेड़-पौधे, झाड़ियां और घास जलकर राख हो चुके हैं, जिससे पूरे पारिस्थितिकी तंत्र पर गहरा असर पड़ रहा है। यह क्षेत्र न केवल जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में भी इसकी अहम भूमिका है। ऐसे में इस तरह की आग का दीर्घकालिक प्रभाव पड़ना तय माना जा रहा है। सबसे ज्यादा चिंता का विषय यहां के वन्यजीव हैं, जो इस आग के कारण अपने प्राकृतिक आवास से बेघर हो रहे हैं। छोटे-बड़े जानवर अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भाग रहे हैं, जिससे उनकी सुरक्षा पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। कई जीव आग की चपेट में आने से घायल हो चुके हैं, जबकि कुछ के मरने की आशंका भी जताई जा रही है। इस स्थिति ने वन्यजीव संरक्षण को लेकर नई चिंता खड़ी कर दी है।

स्थानीय लोगों में भी दहशत का माहौल है, क्योंकि आग तेजी से आबादी वाले क्षेत्रों के करीब पहुंचती जा रही है। हालांकि अभी तक किसी बड़े जनहानि की खबर नहीं है, लेकिन खतरा लगातार बना हुआ है। प्रशासन की ओर से सतर्कता बरतने और लोगों को सुरक्षित रहने की सलाह दी जा रही है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि जल्द ही इस आग पर काबू नहीं पाया गया, तो इसका असर और भी व्यापक हो सकता है। यह न केवल वन क्षेत्र को नुकसान पहुंचाएगा, बल्कि आसपास के पर्यावरण, जल स्रोतों और जैव विविधता पर भी गहरा प्रभाव डालेगा। ऐसे में जरूरी है कि आधुनिक तकनीकों और संसाधनों का उपयोग कर आग बुझाने के प्रयासों को और तेज किया जाए।

कुल मिलाकर, कुंभलगढ़ का यह जंगल इन दिनों एक बड़े संकट से गुजर रहा है, जहां हर गुजरता दिन स्थिति को और गंभीर बना रहा है। प्रशासन और वन विभाग के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस आग को जल्द से जल्द नियंत्रित करने की है, ताकि इस अमूल्य प्राकृतिक धरोहर को और अधिक नुकसान से बचाया जा सके।

प्रयागराज स्टेशन पर नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य के कारण ट्रेनों का मार्ग परिवर्तन

प्रयागराज स्टेशन पर यार्ड रीमॉडलिंग कार्य के तहत नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य किया जाएगा। इसके कारण निम्नलिखित ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से संचालित किया जाएगा—

ट्रेन संख्या 15560 अहमदाबाद–दरभंगा एक्सप्रेस

जो दिनांक 24.04.2026 को अहमदाबाद से प्रस्थान करेगी, अपने निर्धारित मार्ग माणिकपुर–प्रयागराज–प्रयागराज रामबाग–वाराणसी–औंड़िहार के स्थान पर माणिकपुर–प्रयागराज छिवकी–जीवनाथपुर–वाराणसी–जौनपुर–औंड़िहार होकर चलेगी।

ट्रेन संख्या 15559 दरभंगा–अहमदाबाद एक्सप्रेस

जो दिनांक 29.04.2026 को दरभंगा से प्रस्थान करेगी, अपने निर्धारित मार्ग औंड़िहार–वाराणसी–प्रयागराज रामबाग–प्रयागराज–माणिकपुर के स्थान पर औंड़िहार–जौनपुर–वाराणसी–जीवनाथपुर–प्रयागराज छिवकी–माणिकपुर होकर चलेगी।

ट्रेन संख्या 19421 अहमदाबाद–पटना एक्सप्रेस

जो दिनांक 26.04.2026 को अहमदाबाद से प्रस्थान करेगी, अपने निर्धारित मार्ग माणिकपुर–प्रयागराज–प्रयागराज रामबाग–वाराणसी–पं. दीन दयाल उपाध्याय के स्थान पर माणिकपुर–प्रयागराज छिवकी–मिर्जापुर–पं. दीन दयाल उपाध्याय होकर चलेगी।

ट्रेन संख्या 19422 पटना–अहमदाबाद एक्सप्रेस

जो दिनांक 28.04.2026 को पटना से प्रस्थान करेगी, अपने निर्धारित मार्ग पं. दीन दयाल उपाध्याय–वाराणसी–प्रयागराज रामबाग–प्रयागराज–माणिकपुर के स्थान पर पं. दीन दयाल उपाध्याय–मिर्जापुर–प्रयागराज छिवकी–माणिकपुर होकर चलेगी।

ट्रेन संख्या 09447 अहमदाबाद–पटना विशेष ट्रेन

जो दिनांक 29.04.2026 को अहमदाबाद से प्रस्थान करेगी, अपने निर्धारित मार्ग आगरा फोर्ट–टूंडला–प्रयागराज–पं. दीन दयाल उपाध्याय के स्थान पर आगरा कैंट–वीरांगना लक्ष्मीबाई (झांसी)–माणिकपुर–प्रयागराज छिवकी–पं. दीन दयाल उपाध्याय होकर चलेगी।

उपरोक्त सभी ट्रेनों को प्रयागराज छिवकी स्टेशन पर 02 मिनट का अस्थायी ठहराव प्रदान किया गया है।

बाड़मेर में दर्दनाक सड़क हादसा: स्कूल बस को ट्रक की टक्कर, एक की मौत, कई बच्चे गंभीर घायल

बाड़मेर। राजस्थान के बायतू क्षेत्र में बुधवार सुबह एक भीषण सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। बायतू-जोधपुर चौराहे के पास बच्चों को लेने के लिए खड़ी एक निजी स्कूल बस को पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस का पिछला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और मौके पर चीख-पुकार मच गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि कई मासूम बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिससे पूरे क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल बन गया है।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, स्कूल बस रोज की तरह सुबह बच्चों को लेने के लिए सड़क किनारे रुकी हुई थी। बस में करीब दो दर्जन बच्चे सवार थे और कुछ

बच्चे चढ़ने-उतरने की प्रक्रिया में थे, तभी अचानक पीछे से तेज गति से आए ट्रक ने बस को टक्कर मार दी। इस अचानक हुए हादसे से बस में बैठे बच्चों में अफरा-तफरी मच गई और कई बच्चे अपनी सीटों से उछलकर गिर पड़े। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया और घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पताल पहुंचाया।

घायलों को पहले बायतू के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार शुरू किया। हादसे की सूचना मिलते ही बच्चों के परिजन भी अस्पताल पहुंचने लगे, जहां का माहौल बेहद भावुक और तनावपूर्ण हो गया। माता-पिता अपने बच्चों की हालत देखकर बेहद व्यथित नजर आए और कई लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नाराजगी भी जाहिर की। अभिभावकों ने इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

हादसे में घायल हुए 9 बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए जोधपुर के बड़े अस्पताल में रेफर किया गया है। इन बच्चों को फ्रैक्चर और अन्य गंभीर चोटें आई हैं और डॉक्टरों की विशेष टीम उनकी निगरानी कर रही है। अस्पताल प्रशासन ने सभी जरूरी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है और लगातार स्थिति पर नजर रखी जा रही है।

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे क्षेत्र को नियंत्रण में लिया। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में हादसे की मुख्य वजह ट्रक चालक की तेज रफ्तार और लापरवाही मानी जा रही है। हालांकि, पुलिस स्कूल बस के दस्तावेजों की भी जांच कर रही है, जिसमें फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट और चालक की वैधता शामिल है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कहीं किसी स्तर पर नियमों का उल्लंघन तो नहीं हुआ।

घटना के बाद स्थानीय जनप्रतिनिधि और भाजपा नेता बालाराम मूंढ भी मौके पर पहुंचे और अस्पताल जाकर घायलों का हालचाल जाना। उन्होंने डॉक्टरों से इलाज की स्थिति की जानकारी ली और प्रशासन को निर्देश दिए कि सभी घायलों को बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है, ताकि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं से बचा जा सके।

सोना वायदा 1479 रुपये, चांदी वायदा 3885 रुपये और क्रूड ऑयल वायदा 31 रुपये बढ़ा

मुंबईः देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 154721.67 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 20902.72 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 133818.51 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स का अप्रैल वायदा 36894 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 2104.8 करोड़ रुपये का हुआ।

कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 13369.77 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना जून वायदा सत्र के आरंभ में 153335 रुपये के भाव पर खूलकर, 153699 रुपये के दिन के उच्च और 153001 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 151671 रुपये के पिछले बंद के सामने 1479 रुपये या 0.98 फीसदी की बढ़त के साथ 153150 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर कारोबार कर रहा था। गोल्ड-गिनी अप्रैल वायदा 661 रुपये या 0.54 फीसदी की तेजी के संग 122051 रुपये प्रति 8 ग्राम हुआ। गोल्ड-पेटल अप्रैल वायदा 81 रुपये या 0.53 फीसदी की तेजी के संग 15301 रुपये प्रति 1 ग्राम हुआ। सोना-मिनी मई वायदा सत्र के आरंभ में 151299 रुपये के भाव पर खूलकर, 152198 रुपये के दिन के उच्च और 151299 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 1398 रुपये या 0.93 फीसदी की तेजी के संग 151674 रुपये प्रति 10 ग्राम हुआ। गोल्ड-टेन अप्रैल वायदा प्रति 10 ग्राम सत्र के आरंभ में 150748 रुपये के भाव पर खूलकर, 152275 रुपये के दिन के उच्च और 150748 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 150537 रुपये के पिछले बंद के सामने 1237 रुपये या 0.82 फीसदी की तेजी के संग 151774 रुपये प्रति 10 ग्राम हुआ।

चांदी के वायदाओं में चांदी मई वायदा 248717 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 250698 रुपये और नीचे में 248042 रुपये पर पहुंचकर, 244701 रुपये के पिछले बंद के सामने 3885 रुपये या 1.59 फीसदी बढ़कर 248586 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था। इनके अलावा चांदी-मिनी अप्रैल वायदा 3988 रुपये या 1.62 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 250474 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि चांदी-माइक्रो अप्रैल वायदा 3990 रुपये या 1.62 फीसदी बढ़कर 250570 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था।

▸▸ कमोडिटी वायदाओं में 20902.72 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 133818.51 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ टर्नओवर : सोना-चांदी के वायदाओं में 13369.77 करोड़ रुपये का हुआ कारोबार : बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स फ्यूचर्स 36894 पॉइंट के स्तर पर

मेटल वर्ग में 3300.93 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा अप्रैल वायदा 11.7 रुपये या 0.92 फीसदी की तेजी के संग 1276.75 रुपये प्रति किलो हुआ। जबकि जस्ता अप्रैल वायदा 5.85 रुपये या 1.7 फीसदी की तेजी के संग 349.3 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचा। इसके सामने एल्यूमीनियम अप्रैल वायदा 5.9 रुपये या 1.62 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 371.2 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि सीसा अप्रैल वायदा 30 पैसे या 0.15 फीसदी टूटकर 196.15 रुपये प्रति किलो हुआ।

इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 4174.22 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल मई वायदा सत्र के आरंभ में 8391 रुपये के भाव पर खूलकर, 8604 रुपये के दिन के उच्च और 8240 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 31 रुपये या 0.37 फीसदी की तेजी के संग 8468 रुपये प्रति बैरल हुआ। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी मई वायदा 25 रुपये या 0.3 फीसदी की तेजी के संग 8465 रुपये प्रति बैरल के भाव पर पहुंचा। इनके अलावा नैचुरल गैस अप्रैल वायदा सत्र के आरंभ में 254.2 रुपये के भाव पर खूलकर, 257 रुपये के दिन के उच्च और 253.8 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 252.3 रुपये के पिछले बंद के सामने 3.2 रुपये या 1.27 फीसदी की तेजी के संग 255.5 रुपये प्रति एमएमबीटीयू हुआ। जबकि नैचुरल गैस-मिनी अप्रैल वायदा 3.2 रुपये या 1.27 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 255.6 रुपये प्रति एमएमबीटीयू पर आ गया।

कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल अप्रैल वायदा सत्र के आरंभ में 1009 रुपये के भाव पर खूलकर, 1.7 रुपये या 0.17 फीसदी की गिरावट के साथ 1002 रुपये प्रति किलो के भाव पर कारोबार कर रहा था।

कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सोना के विभिन्न अनुबंधों में 6877.48 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 6492.29 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 2277.72 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 590.36 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 15.04 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 407.23 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 3095.82 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 1067.25 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। मेंथा ऑयल के वायदा में 5.12 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। जबकि कॉटन कैंडी के वायदाओं में 0.07 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 9767 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 59504 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 27890 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 376557 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 64587 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 7960 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 25565 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 92671 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 15096 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 35405 लोट के स्तर पर था।

इंडेक्स फ्यूचर्स में बुलडेक्स अप्रैल वायदा 36894 पॉइंट पर खूलकर, 36894 के उच्च और 36848 के नीचले स्तर को छूकर, 131 पॉइंट बढ़कर 36894 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था।

कमोडिटी ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स में क्रूड ऑयल मई 10000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति बैरल 14.2 रुपये की गिरावट के साथ 344 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस अप्रैल 255 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 1.05 रुपये की बढ़त के साथ 4.25 रुपये हुआ।

सोना अप्रैल 155000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 180 रुपये की बढ़त के साथ 1305.5 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी अप्रैल 255000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 101.5 रुपये की बढ़त के साथ 1331 रुपये हुआ। तांबा अप्रैल 1300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 69 पैसे के सुधार के साथ 2.53 रुपये हुआ। जस्ता अप्रैल 330 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 6.56 रुपये की बढ़त के साथ 18.91 रुपये हुआ।

पुट ऑप्शंस में क्रूड ऑयल मई 7000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति बैरल 13.8 रुपये की गिरावट के साथ 139.2 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस अप्रैल 255 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 2.25 रुपये की गिरावट के साथ 3.6 रुपये हुआ।

सोना अप्रैल 145000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 247.5 रुपये की गिरावट के साथ 373 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी अप्रैल 240000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 1502.5 रुपये की गिरावट के साथ 1000.5 रुपये हुआ। तांबा अप्रैल 1050 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 12 पैसे की नरमी के साथ 0.1 रुपये हुआ। जस्ता अप्रैल 330 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 32 पैसे की नरमी के साथ 0.03 रुपये हुआ।

ड्यूटी भी निभाई, लोकतंत्र का फर्ज भी... सूरत में पोस्टल बैलेट से मतदान की शुरुआत

सूरत। चुनाव केवल एक दिन का आयोजन नहीं होता, बल्कि यह एक सतत प्रक्रिया है जिसमें हर उस व्यक्ति की भागीदारी जरूरी होती है, जो लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपनी भूमिका निभाता है। इसी भावना को साकार करते हुए गुजरात के सूरत में लोकल बॉडी चुनाव और उपचुनाव से पहले पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। शहर के पुलिस हेडक्वार्टर में बुधवार सुबह से ही एक अलग ही माहौल देखने को मिला, जहां सुरक्षा व्यवस्था संभालने वाले पुलिसकर्मी और अन्य सरकारी कर्मचारी अपने कर्तव्यों के साथ-साथ अपने मतदान के अधिकार का भी जिम्मेदारी से निर्वहन करते नजर आए। सुबह 9 बजे से ही मतदान प्रक्रिया शुरू हुई, पुलिस हेडक्वार्टर परिसर में कतारें लगनी शुरू हो गईं। यहां मौजूद कर्मचारी पूरी गंभीरता और उत्साह के साथ अपने वोट डालने पहुंचे। आम तौर पर चुनाव के दिन ये वही लोग होते हैं जो दूसरों को सुरक्षित मतदान का अवसर देने के लिए खुद ड्यूटी पर तैनात रहते हैं और अपने मताधिकार का उपयोग नहीं कर पाते। ऐसे में पोस्टल बैलेट की यह सुविधा उनके लिए लोकतंत्र से जुड़ने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन जाती है। इस बार भी यही देखने को मिला, जब बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने इस व्यवस्था का लाभ उठाकर मतदान किया।

इस पूरी प्रक्रिया को भारतीय चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के तहत आयोजित किया जा रहा है, जिसमें पारदर्शिता और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया है। चुनाव आयोग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र मतदाता केवल इसलिए मतदान से वंचित न रह जाए, क्योंकि वह

चुनावी ड्यूटी में व्यस्त है। यही कारण है कि पोस्टल बैलेट जैसी व्यवस्थाएं लगातार मजबूत की जा रही हैं, ताकि हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। सूरत जिले में इस बार करीब 5 हजार कर्मचारी पोस्टल बैलेट के जरिए वोट डालने वाले हैं। इनमें पुलिस बल, होमगार्ड और अन्य आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मचारी शामिल हैं, जिनकी जिम्मेदारी चुनाव के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखना होती है। ये वही लोग हैं जो मतदान केंद्रों पर सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, भीड़ को नियंत्रित करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। ऐसे में उनका मतदान करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे भी इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बराबर के हिस्सेदार हैं।

पुलिस हेडक्वार्टर को इस अवसर के लिए विशेष मतदान केंद्र के रूप में तैयार किया गया है। यहां अलग-अलग सेक्शन बनाए गए हैं, ताकि मतदान प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित हो सके और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी खुद मौके पर मौजूद रहकर व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहे हैं। इससे यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि हर चरण नियमों के अनुसार पूरा हो और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की संभावना न रहे।

मतदान प्रक्रिया के दौरान पारदर्शिता बनाए रखने के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। पूरे मतदान केंद्र के बाहर वीडियोग्राफी की जा रही है, ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोका जा सके और जरूरत पड़ने पर उसका रिकॉर्ड उपलब्ध रहे। यह कदम न केवल प्रक्रिया को सुरक्षित बनाता है, बल्कि इससे मतदाताओं का विश्वास भी बढ़ता है कि उनका वोट पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय है।

पोस्टल बैलेट के महत्व को समझना भी जरूरी है, क्योंकि ये वोट चुनाव परिणामों में अहम भूमिका निभाते हैं। चुनाव नियमों के अनुसार, मतगणना के दिन सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जाती है। ऐसे में यह वोट शुरुआती रुझानों को प्रभावित कर सकते हैं और कई बार चुनाव की दिशा तय करने में भी महत्वपूर्ण साबित होते हैं। यही कारण है कि इन बैलेट पेपर की सुरक्षा और समय पर काउंटिंग सेंटर तक पहुंचाने के लिए प्रशासन विशेष सतर्कता बरतता है।

मतदान के बाद सभी बैलेट पेपर को सुरक्षित तरीके से सील करके स्ट्रॉन्ग रूम में रखा जाता है, जहां उनकी सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए जाते हैं। इसके बाद निर्धारित समय पर इन्हें मतगणना केंद्र तक पहुंचाया जाता है, जहां गिनती की प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न होती है। इस पूरी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि यह सीधे चुनाव परिणामों को प्रभावित कर सकती है।

सूरत में शुरू हुई यह प्रक्रिया एक बार फिर यह दर्शाती है कि लोकतंत्र केवल आम नागरिकों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें हर उस व्यक्ति की भागीदारी जरूरी है, जो उस व्यवस्था को चलाने में अपनी भूमिका निभाता है। पुलिसकर्मी और सरकारी कर्मचारी, जो आमतौर पर दूसरों की सुरक्षा और सुविधा के लिए काम करते हैं, जब खुद मतदान करते हैं तो यह लोकतंत्र के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है।

आने वाले दिनों में जैसे-जैसे मतदान की तारीख नजदीक आएगी, वैसे-वैसे चुनावी गतिविधियां और तेज होंगी। लेकिन सूरत में पोस्टल बैलेट के जरिए शुरू हुई यह पहल पहले ही यह संकेत दे चुकी है कि इस बार चुनावी प्रक्रिया को अधिक समावेशी और प्रभावी बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। यह न केवल एक प्रशासनिक व्यवस्था है, बल्कि लोकतंत्र के प्रति एक मजबूत संदेश भी है कि हर वोट मायने रखता है, चाहे वह किसी भी माध्यम से क्यों न डाला गया हो।

दो मंज़िला सफर की नई उड़ान, सूरत में दौड़ी इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस ने बदली शहर की रफ्तार

सूरत। चुनावी सरगर्मी के बीच जब सड़कों पर राजनीतिक हलचल अपने चरम पर है, उसी समय गुजरात के सूरत शहर ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में एक नई और आकर्षक शुरुआत की झलक देखी। पहली बार शहर की सड़कों पर डबल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बस का ट्रायल रन किया गया, जिसने न केवल लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा बल्कि शहर के भविष्य के परिवहन मॉडल को लेकर नई उम्मीदें भी जगा दीं। स्टेशन से कामरेज तक चले इस ट्रायल के दौरान जहां एक ओर तकनीकी परीक्षण किए गए, वहीं दूसरी ओर आम नागरिकों में इस अनोखी बस को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला।

यह ट्रायल गुजरात स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन द्वारा किया गया, जिसमें बस को स्टेशन से कोसाड होते हुए कामरेज तक चलाया गया। इस दौरान इंजीनियरों की टीम ने हर छोटे-बड़े पहलू का बारीकी से निरीक्षण किया। खासतौर पर शहर के पुलों की ऊंचाई, सड़कों के मोड़, ट्रैफिक की स्थिति और बस की गतिशीलता पर विशेष ध्यान दिया गया। यह पूरी कवायद इसलिए की गई ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भविष्य में जब यह बस नियमित रूप से सड़कों पर उतरे, तो किसी भी प्रकार की तकनीकी या संरचनात्मक बाधा सामने न आए।

डबल डेकर बस का यह ट्रायल केवल

एक परीक्षण नहीं था, बल्कि यह सूरत के परिवहन ढांचे में आने वाले बड़े बदलाव का संकेत भी है। नगर निगम की योजना के अनुसार, आने वाले समय में शहर को दो स्थायी डबल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बसें मिलने की संभावना है। इन बसों को खास तौर पर उन मार्गों पर चलाने की योजना बनाई जा रही है, जहां यात्री संख्या अधिक होती है और जहां शहर के दर्शनीय स्थलों का आकर्षण भी जुड़ा हुआ है। विशेष रूप से डुमस बीच जैसे पर्यटन स्थलों के लिए इन बसों का उपयोग किया जाएगा, ताकि यात्री ऊपरी डेक से शहर और समुद्र का खूबसूरत नजारा देख सकें।

इस परियोजना के पीछे एक व्यापक दृष्टिकोण भी काम कर रहा है। सूरत पहले से ही इलेक्ट्रिक बसों के मामले में देश के अग्रणी शहरों में गिना जाता है, जहां करीब 450 इलेक्ट्रिक बसें पहले से संचालित हो रही हैं। अब केंद्र सरकार की ई-ड्राइव योजना के तहत 600 और बसों को जोड़ने की तैयारी है। ऐसे में डबल डेकर बसों का शामिल होना न केवल इस नेटवर्क को और मजबूत करेगा, बल्कि शहर के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को एक नई पहचान भी देगा। यह कदम पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने के साथ-साथ यात्रियों को एक बेहतर और आधुनिक अनुभव प्रदान करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

बताया जा रहा है कि इन बसों की खरीद प्रक्रिया अंतिम चरण में है और इन्हें Switch Mobility से उसी दर पर खरीदा जाएगा, जिस पर जीएसआरटीसी ने पहले ही ऑर्डर दिया है। इस डील की खास बात यह है कि इसमें केवल बसों की खरीद ही नहीं, बल्कि 10 साल का मेंटेनेंस और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल है। इसका मतलब यह है कि शहर को न केवल नई बसें मिलेंगी, बल्कि उनके सुचारू संचालन के लिए आवश्यक सभी व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित की जाएंगी।

ट्रायल के दौरान सूरत की सड़कों पर जो दृश्य देखने को मिला, वह अपने आप में खास था। जैसे ही यह दो मंज़िला बस शहर के विभिन्न इलाकों से गुजरी, लोग अपने-अपने काम छोड़कर इसे देखने के लिए रुक गए। कई जगहों पर भीड़ जमा हो गई, जहां लोगों ने बस के साथ सेल्फी ली और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा किए। खासकर बच्चों और युवाओं में इस नई सवारी को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा गया। उनके लिए यह केवल एक बस नहीं, बल्कि एक नया अनुभव था, जो अब तक उन्होंने केवल बड़े महानगरों में ही देखा था।

इस पहल का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह शहर के बढ़ते यातायात दबाव को कम करने में भी सहायक साबित हो सकती है। डबल डेकर बसें एक ही समय में अधिक यात्रियों को ले जाने में सक्षम होती हैं, जिससे सड़कों पर वाहनों की संख्या कम हो सकती है। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक होने के कारण यह बसें प्रदूषण को भी कम करेंगी, जो तेजी से बढ़ते शहरीकरण के बीच एक बड़ी चुनौती बन चुका है। सूरत में इस ट्रायल ने यह स्पष्ट कर दिया है कि शहर केवल औद्योगिक और आर्थिक विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि वह आधुनिक और टिकाऊ शहरी परिवहन की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है।

आने वाले समय में जब ये डबल डेकर बसें नियमित रूप से सड़कों पर दौड़ेंगी, तब यह न केवल शहर की पहचान बनेंगी, बल्कि लोगों के दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी बन जाएंगी। यह पहल सूरत को एक स्मार्ट और पर्यावरण के प्रति सजग शहर के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक मजबूत कदम मानी जा रही है।

नए सपनों की उजली शुरुआत, केन्द्रीय विद्यालय ओएनजीसी सूरत में प्रवेशोत्सव बना उत्सव का रंग

सूरत। शिक्षा केवल किताबों और कक्षाओं तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह एक ऐसा अनुभव है जो बच्चों के जीवन की पहली सीढ़ी से ही उनके व्यक्तित्व को आकार देना शुरू कर देता है। इसी सोच को साकार करते हुए सूरत स्थित केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 3 ओएनजीसी सूरत में कक्षा 1 के नवप्रवेशी विद्यार्थियों के लिए प्रवेशोत्सव का आयोजन बेहद उत्साह और गरिमा के साथ किया गया। यह कार्यक्रम केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं था, बल्कि बच्चों और उनके अभिभावकों के लिए एक ऐसा अनुभव बना, जिसने स्कूल जीवन की शुरुआत को यादगार बना दिया।

कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय के प्राचार्य राजेश कुमार के स्वागत भाषण से हुई, जिसमें उन्होंने सभी नवप्रवेशी विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों का गर्मजोशी से स्वागत किया। उनके शब्दों में न केवल विद्यालय की प्रतिबद्धता झलक रही थी, बल्कि यह भी स्पष्ट था कि संस्था बच्चों के समग्र विकास को प्राथमिकता देती है। उन्होंने अभिभावकों को यह भरोसा दिलाया कि विद्यालय केवल शिक्षा ही नहीं, बल्कि संस्कार, आत्मविश्वास और रचनात्मकता को भी समान महत्व देता है।

इसके बाद कार्यक्रम का माहौल तब और भी जीवंत हो गया जब प्राथमिक

अनुभाग के छोटे-छोटे विद्यार्थियों ने मधुर स्वागत गीत प्रस्तुत किया। बच्चों की मासूम आवाज और उनके उत्साह ने पूरे वातावरण को आनंदमय बना दिया। यह प्रस्तुति न केवल नए छात्रों के लिए स्वागत का प्रतीक थी, बल्कि यह भी दर्शाती थी कि विद्यालय में कला और अभिव्यक्ति को कितना महत्व दिया जाता है।

कार्यक्रम के अगले चरण में प्राथमिक अनुभाग की प्रभारी दक्षा गुप्ता ने अभिभावकों को विद्यालय की कार्यप्रणाली, नियमों और प्रक्रियाओं से विस्तार से अवगत कराया। उन्होंने विशेष रूप से नई शिक्षा नीति 2020 के दृष्टिकोण को समझाते हुए बताया कि कैसे यह नीति बच्चों के सर्वांगीण विकास पर केंद्रित है। इसके साथ ही उन्होंने फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी (FLN) और 'विद्या प्रवेश' मॉड्यूल की जानकारी देते हुए यह स्पष्ट किया कि प्रारंभिक शिक्षा को मजबूत बनाना ही आगे की सफलता की नींव तैयार करता है।

कार्यक्रम के दौरान एक आकर्षक प्रस्तुति के माध्यम से FLN और क्रिएटिव लर्निंग एक्टिविटीज (CLA) के अंतर्गत संचालित गतिविधियों को भी प्रदर्शित किया गया। इस प्रस्तुति ने अभिभावकों को यह समझने में मदद की कि विद्यालय किस तरह बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को रोचक और प्रभावी बनाने के लिए आधुनिक तरीकों का उपयोग कर रहा है। अभिभावकों ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की दिशा में एक सकारात्मक कदम बताया।

इस पूरे आयोजन का सबसे आकर्षक हिस्सा रचनात्मक सेल्फी बूथ रहा, जिसने कार्यक्रम को एक उत्सव का रूप दे दिया। यहां बच्चों और उनके अभिभावकों ने उत्साहपूर्वक तस्वीरें खिंचवाईं और इस खास दिन को यादगार बना लिया। यह पहल न केवल बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाने का माध्यम बनी, बल्कि इससे अभिभावकों और विद्यालय के बीच एक आत्मीय संबंध भी स्थापित हुआ।

कार्यक्रम के दौरान नवप्रवेशी विद्यार्थियों को 'विद्या प्रवेश' गतिविधि पुस्तिका, विद्यालय डायरी और उपहार भी वितरित किए गए। ये सामग्री केवल औपचारिक वस्तुएं नहीं थीं, बल्कि बच्चों के सीखने के सफर की पहली साथी बनकर उनके साथ जुड़ने वाली थीं। इससे बच्चों में विद्यालय के प्रति उत्साह और अपनापन और भी बढ़ गया। कार्यक्रम के अंत में पीजीटी (बायोलॉजी) एवं प्रवेश प्रभारी अंजना बुंदेला ने सभी उपस्थित अभिभावकों, विद्यार्थियों और स्टाफ का आभार व्यक्त किया। उनके धन्यवाद ज्ञापन के साथ ही कार्यक्रम का समापन हुआ, लेकिन इसके साथ ही एक नई शुरुआत का द्वार भी खुल गया। यह प्रवेशोत्सव केवल एक आयोजन नहीं था, बल्कि यह बच्चों के जीवन के एक महत्वपूर्ण अध्याय की शुरुआत का प्रतीक था। इस कार्यक्रम ने यह स्पष्ट कर दिया कि जब शिक्षा को उत्सव के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, तो वह बच्चों के मन में गहरी छाप छोड़ती है और उन्हें सीखने के लिए प्रेरित करती है। सूरत के इस विद्यालय ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि शिक्षा केवल ज्ञान देने का माध्यम नहीं, बल्कि जीवन को संवारने की प्रक्रिया है, जिसे जितना आनंदमय बनाया जाए, उतना ही उसका प्रभाव गहरा होता है।

सूरत के सचिन GIDC में सुरक्षा को नई मजबूती, 7.50 करोड़ से बनेगा अत्याधुनिक फायर स्टेशन

सूरत के तेजी से विकसित होते औद्योगिक क्षेत्र सचिन GIDC में अब सुरक्षा व्यवस्था को नई मजबूती देने की दिशा में एक बड़ा और निर्णायक कदम उठाया गया है। लगातार बढ़ते उद्योग, हजारों श्रमिकों की आवाजाही और उत्पादन इकाइयों की घनी मौजूदगी के बीच आग जैसी आपात स्थितियों का खतरा हमेशा बना रहता है। इसी को ध्यान में रखते हुए यहां एक अत्याधुनिक एडिशनल फायर स्टेशन और फायर स्टाफ क्वार्टर के निर्माण कार्य की शुरुआत की गई है, जो करीब 7.50 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया जाएगा। यह परियोजना केवल एक इमारत का निर्माण नहीं, बल्कि पूरे औद्योगिक क्षेत्र के लिए एक मजबूत सुरक्षा ढांचा तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।

यह नया फायर स्टेशन रोड नंबर-1 स्थित मौजूदा फायर स्टेशन के ठीक पास विकसित किया जा रहा है, ताकि आपात स्थिति में संसाधनों का बेहतर समन्वय हो सके और प्रतिक्रिया समय को न्यूनतम किया जा सके। योजना

के अनुसार, इस फायर स्टेशन को आधुनिक तकनीक और सुविधाओं से पूरी तरह लैस किया जाएगा। ग्राउंड फ्लोर पर चार बड़े वॉटर बाउज़र (पानी के टैंकर) खड़े करने की व्यवस्था होगी, जिससे किसी भी बड़े अग्निकांड की स्थिति में तुरंत और पर्याप्त पानी उपलब्ध कराया जा सके। प्रथम मंजिल पर एक अत्याधुनिक कमांड रूम बनाया जाएगा, जहां से पूरे क्षेत्र में होने वाली घटनाओं की निगरानी और फायर ऑपरेशन को कंट्रोल किया जाएगा। यह कमांड सेंटर आधुनिक संचार प्रणाली और निगरानी उपकरणों से सुसज्जित होगा, जिससे किसी भी आपात स्थिति में त्वरित निर्णय लेना संभव हो सकेगा।

दूसरी मंजिल पर फायर कर्मियों के लिए मेस रूम की सुविधा विकसित की जाएगी, जिससे ड्यूटी के दौरान उन्हें बेहतर आराम और भोजन की व्यवस्था मिल सके। इसके अलावा, इस परियोजना का एक अहम हिस्सा फायर स्टाफ के लिए आवासीय सुविधा भी है। ग्राउंड प्लस दो मंजिला आवासीय क्वार्टर बनाए जाएंगे, जिनमें कुल 12 एक बीएचके यूनिट्स शामिल होंगी। यह व्यवस्था इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि आपातकालीन सेवाओं में समय सबसे बड़ा कारक होता है। जब फायर कर्मी अपने कार्यस्थल के पास ही रहेंगे, तो किसी भी घटना की सूचना मिलते ही वे तुरंत मौके पर पहुंच सकेंगे, जिससे जान-माल के नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकेगा।

इस परियोजना का शिलान्यास सचिन नोटिफाइड एरिया के चेयरमैन और सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट नीलेशभाई गामी के करकमलों द्वारा किया गया। इस अवसर पर सचिन इंडस्ट्रियल सोसाइटी के प्रेसिडेंट किशोर पटेल, सेक्रेटरी मयूर गोलवाला, डायरेक्टर गौरांग चपटवाला, भीखूभाई नकरानी, मुकेश चतुर्वेदी, हेमंत जरीवाला और मैनेजर अरविंद अहीर सहित कई गणमान्य लोग और स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे। सभी ने इस परियोजना को औद्योगिक सुरक्षा के लिए मील का पत्थर बताया और उम्मीद जताई कि इससे क्षेत्र में सुरक्षा मानकों को नई ऊंचाई मिलेगी।

दरअसल, सचिन GIDC क्षेत्र गुजरात के प्रमुख औद्योगिक हब में से एक है, जहां टेक्सटाइल, केमिकल, इंजीनियरिंग और अन्य कई क्षेत्रों की सैकड़ों फैक्ट्रियां संचालित होती हैं। इन उद्योगों में ज्वलनशील पदार्थों का उपयोग होने के कारण आग लगने की घटनाओं का खतरा हमेशा बना रहता है। पहले कई बार ऐसा देखा गया है कि आग लगने की स्थिति में फायर ब्रिगेड को दूर-दराज के इलाकों से पहुंचना पड़ता था, जिससे राहत और बचाव कार्य में देरी होती थी। लेकिन अब इस नए फायर स्टेशन के निर्माण से न केवल प्रतिक्रिया समय घटेगा, बल्कि आपात स्थिति से निपटने की क्षमता भी कई गुना बढ़ जाएगी।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के अत्याधुनिक फायर स्टेशन औद्योगिक क्षेत्रों के लिए अनिवार्य होते जा रहे हैं। यह न केवल आग लगने की घटनाओं को नियंत्रित करने में मदद करते हैं, बल्कि उद्योगों के प्रति निवेशकों का भरोसा भी बढ़ाते हैं। जब किसी क्षेत्र में मजबूत सुरक्षा व्यवस्था होती है, तो वहां उद्योगों का विस्तार और निवेश भी तेजी से होता है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है।

कुल मिलाकर, यह परियोजना सचिन GIDC क्षेत्र के लिए एक बड़ी राहत और सुरक्षा का प्रतीक बनकर उभर रही है। आने वाले समय में यह फायर स्टेशन न केवल आग जैसी आपदाओं से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, बल्कि हजारों श्रमिकों और उद्योगों के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच भी साबित होगा। यह पहल इस बात का भी संकेत है कि अब औद्योगिक विकास के साथ-साथ सुरक्षा और आपदा प्रबंधन को भी उतनी ही प्राथमिकता दी जा रही है, जो किसी भी विकसित और सुरक्षित औद्योगिक क्षेत्र की पहचान होती है।

पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची विवाद: लाखों लोगों के मताधिकार से वंचित होने की आशंका

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। पश्चिम बंगाल में मतदान के लिए केवल कुछ ही घंटे शेष हैं, ऐसे में चुनाव आयोग के अक्षम प्रशासन या किसी के इशारे पर काम करने में उसकी गैर-निष्पक्षता ने एक गंभीर स्थिति पैदा कर दी है, जहां लाखों नागरिक "मतदान" से वंचित हैं, जो लोकतंत्र का एक प्रमुख स्तंभ है।

पश्चिम बंगाल के चुनाव दो विरोधी विचारधाराओं के बीच एक बड़ा संघर्ष है और पूरा देश इसे देख रहा है। अगर इस महत्वपूर्ण चुनाव में लाखों योग्य मतदाताओं को उनके पवित्र संवैधानिक मताधिकार से वंचित किया जाता है, तो यह लोकतंत्र के लिए कलंक होगा। सवाल यह है कि अगर चुनाव आयोग की निष्क्रियता के कारण लाखों योग्य मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, तो क्या परिणाम को निष्पक्ष या सही माना जा सकता है? मतदाता सूचियों के विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) की प्रक्रिया के कारण पश्चिम बंगाल में उत्पन्न जटिलताओं ने आशंका पैदा कर दी है कि लाखों मतदाता अपने मताधिकार से वंचित हो सकते हैं। और चूंकि इस मुद्दे पर पूरे राज्य में जन आक्रोश है, इसलिए सवाल यह है कि अगर किसी कारणवश बाद में योग्य पाए गए मतदाताओं को मतदान से रोका जाता है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा?

समस्या यह है कि पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को मतदान होना है। फिर भी, बड़ी संख्या में नागरिक मतदाता सूची से बाहर हैं। लोगों के मतदान के अधिकार की रक्षा के लिए बनाई गई प्रक्रिया पर उठ रहे सवाल लोकतंत्र और संवैधानिक अधिकारों के दृष्टिकोण से बेहद चिंताजनक हैं। इस बात से शायद ही कोई असहमत होगा कि किसी भी अयोग्य व्यक्ति को मतदान का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। इसी तरह, किसी भी योग्य मतदाता को मात्र तकनीकी खामियों और जटिलताओं के आधार पर उसके मतदान के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।

अजमेर-पालनपुर रेलखण्ड पर ब्लॉक के कारण रेल सेवाएँ प्रभावित

अजमेर मण्डल के अजमेर–पालनपुर रेलखण्ड के मध्य जवाली–रानी स्टेशनों के बीच ब्रिज संख्या 633 व 634 पर आरसीसी बॉक्स डालने हेतु ब्लॉक लिया जा रहा है, जिसके कारण रेल यातायात प्रभावित रहेगा। विवरण निम्नानुसार हैः

रद्द ट्रेनें

- ट्रेन सं. 14822 साबरमती–जोधपुर एक्सप्रेस, दिनांक 24.04.26 व 25.04.26 को रद्द रहेगी।
- ट्रेन सं. 14821 जोधपुर–साबरमती एक्सप्रेस, दिनांक 23.04.26 व 24.04.26 को रद्द रहेगी।

मार्ग परिवर्तित ट्रेनें

- ट्रेन सं. 20943 (बान्द्रा टर्मिनस–भगत की कोठी), जो दिनांक 23.04.26 को बान्द्रा टर्मिनस से प्रस्थान करेगी, परिवर्तित मार्ग महेसाना–भीलड़ी–लूनी होकर संचालित होगी। मार्ग में यह ट्रेन पाटन, भीलड़ी, मारवाड़ भीनमाल, जालोर, समदड़ी स्टेशनों पर रुकेगी।
- ट्रेन सं. 20694 (बैंगलुरू–जोधपुर), जो दिनांक 22.04.26 को बैंगलुरू से प्रस्थान करेगी, परिवर्तित मार्ग महेसाना–भीलड़ी–लूनी होकर संचालित होगी। मार्ग में यह ट्रेन पाटन, भीलड़ी, मारवाड़ भीनमाल, जालोर, समदड़ी स्टेशनों पर रुकेगी।
- ट्रेन सं. 20496 (हडपसर–जोधपुर), जो दिनांक 23.04.26 को हडपसर से प्रस्थान करेगी, परिवर्तित मार्ग महेसाना–भीलड़ी–लूनी होकर संचालित होगी। मार्ग में यह ट्रेन पाटन, भीलड़ी, मारवाड़ भीनमाल, जालोर, समदड़ी स्टेशनों पर रुकेगी।
- ट्रेन सं. 14701 (श्रीगंगानगर–बान्द्रा टर्मिनस), जो दिनांक 23.04.26 को श्रीगंगानगर से प्रस्थान करेगी, परिवर्तित मार्ग अजमेर–चित्तौड़गढ़–रतलाम–वडोदरा होकर संचालित होगी। मार्ग में यह ट्रेन भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, नीमच, मंदसौर स्टेशनों पर रुकेगी।

रीशेड्यूल ट्रेनें

- ट्रेन सं. 19411 (गांधीनगर कैपिटल–दौलतपुर चौक), दिनांक 24.04.26 को अपने निर्धारित समय से 01 घंटे 30 मिनट की देरी से प्रस्थान करेगी।
- ट्रेन सं. 19223 (साबरमती–जम्मूतवी), दिनांक 24.04.26 को अपने निर्धारित समय से 01 घंटे की देरी से प्रस्थान करेगी।

दूध की हर बूंद के साथ लोकतंत्र का संदेश, जामकंडोरना में 'निर्भय मतदान' की अनोखी मुहिम

राजकोट। लोकतंत्र केवल चुनावी प्रक्रिया नहीं, बल्कि नागरिकों की भागीदारी और जागरूकता का जीवंत प्रतीक होता है, और जब आम जन खुद इस जिम्मेदारी को समझकर आगे बढ़ते हैं तो लोकतंत्र और भी मजबूत बनता है। गुजरात के राजकोट जिले के जामकंडोरना तालुका में इन दिनों कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है, जहां दूध की आपूर्ति से जुड़ी साधारण-सी लगने वाली सहकारी समितियां लोकतंत्र को सशक्त करने का बड़ा अभियान चला रही हैं। 26 अप्रैल को होने वाले स्थानीय स्वशासन चुनावों से पहले यहां की मिल्क सोसाइटियों ने मतदाता जागरूकता को एक नई दिशा दी है, जो न केवल अनोखी है बल्कि प्रेरणादायक भी है।

जामकंडोरना की इन सहकारी संस्थाओं ने यह साबित कर दिया है कि जागरूकता केवल बड़े मंचों या सरकारी कार्यक्रमों तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह रोजमर्रा की जिंदगी के छोटे-छोटे माध्यमों से भी लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंच सकती है। दूध मंडलियों के सदस्य, जो आमतौर पर अपने व्यवसाय तक ही सीमित रहते हैं,

अब लोकतंत्र के प्रहरी बनकर सामने आए हैं। उन्होंने न केवल खुद मतदान करने का संकल्प लिया है, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी निर्भय होकर वोट देने के लिए प्रेरित करना शुरू कर दिया है।

इस अभियान की सबसे खास बात यह है कि इसमें 'निर्भय मतदान' पर विशेष जोर दिया जा रहा है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत मतदाता की स्वतंत्रता होती है, और जब कोई व्यक्ति बिना किसी दबाव, भय या लालच के अपना मत देता है, तभी चुनाव की वास्तविक निष्पक्षता सामने आती है। इसी भावना को केंद्र में रखते हुए जामकंडोरना की मिल्क सोसाइटियों ने अपने सदस्यों को शपथ दिलाई है कि वे किसी भी प्रकार के दबाव से मुक्त होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। यह शपथ केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि एक सामाजिक संदेश बन चुकी है, जो गांव-गांव और घर-घर तक पहुंच रहा है।

इस पूरे अभियान में जामकंडोरना कोऑपरेटिव सोसाइटी की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है। सोसाइटी ने मतदाता जागरूकता को लेकर जिस तरह की रचनात्मक पहल की है, वह अन्य क्षेत्रों के लिए भी एक उदाहरण बन सकती है। दूध वितरण जैसी रोजमर्रा की प्रक्रिया को उन्होंने एक जन-जागरूकता अभियान में बदल दिया है। सोसाइटी से जुड़े लोग न केवल अपने परिवारों को मतदान के लिए प्रेरित कर रहे हैं, बल्कि वे हर उस व्यक्ति तक यह संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे उनका प्रतिदिन संपर्क होता है।

इस पहल का एक और रोचक पहलू यह है कि दूध आपूर्ति करने वाले सदस्यों को जो पर्चियां दी जाती हैं, उन पर अब मतदान से संबंधित संदेश भी छापे जा रहे हैं। यह एक छोटा-सा कदम लग सकता है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत व्यापक है। हर दिन हजारों लोग इन पर्चियों के संपर्क में आते हैं, और जब वे उस पर 'मेरा वोट, मेरा अधिकार' जैसे संदेश देखते हैं, तो उनके मन में मतदान को लेकर जागरूकता स्वतः ही बढ़ने लगती है। यह तरीका न केवल सरल है, बल्कि बेहद प्रभावी भी है, क्योंकि यह सीधे लोगों के दैनिक जीवन का हिस्सा बन जाता है। जामकंडोरना की यह पहल इस बात का भी संकेत देती है कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए केवल सरकारी प्रयास ही पर्याप्त नहीं होते, बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों की सक्रिय भागीदारी भी जरूरी होती है। जब किसान, व्यापारी, मजदूर और आम नागरिक इस प्रक्रिया में शामिल होते हैं, तब ही चुनाव वास्तव में जन-आंदोलन का रूप ले पाता है। यहां की मिल्क सोसाइटियों ने यही काम किया है—उन्होंने मतदान को एक सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में प्रस्तुत किया है, जिसे हर नागरिक को निभाना चाहिए।

स्थानीय चुनावों में सामान्य वर्ग के उम्मीदवार आगे, पारिवारिक सदस्यों के बीच भी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। गुजरात में स्थानीय निकाय चुनावों में इस बार आरक्षित सीटों पर सामान्य वर्ग, गरीब वर्ग और श्रमिक वर्ग के उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने का मौका मिला है और राजनीतिक दलों ने इन उम्मीदवारों का चयन कर लिया है। भाजपा ने अहमदाबाद के विश्व प्रसिद्ध गुर्जरी बाजार में कालीन बिछाने का काम करने वाली आशा दंतानी, कलोल की एक फैक्ट्री में झाड़ू बनाने का काम करने वाली उषा चौहान, मेहसाना स्थित भाजपा कार्यालय में चपरासी का काम करने वाले रमेश चंद्र भील, वडोदरा के स्कूल वैन चालक भूपेंद्र मच्छी और अहमदाबाद के रिक्शा चालक दशरथ पटनी को मैदान में उतारा है।

दूसरी ओर, घर के सदस्य चुनावी मैदान में एक-दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। सुरेंद्रनगर में सास आम आदमी पार्टी (आप) से और बहू भाजपा से चुनाव लड़ रही हैं। अमरेली में देरानी और जेठानी आमने-सामने हैं। जेठानी भाजपा से और देरानी कांग्रेस से चुनाव लड़ रही हैं। अन्य राज्यों में कॉलेज के छात्र भी चुनाव लड़ने के मूड में हैं। भावनगर की कॉलेज छात्रा आर्ची कुकड़िया कांग्रेस से चुनाव लड़ रही हैं, वहीं बगसारा में रहने वाले और नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे विश्व नाकुम

भाजपा उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं।

इस प्रकार, वर्तमान नगरपालिका, नगर पालिका, तालुका पंचायत और जिला पंचायत चुनावों के परिणाम चटनी की चटनी की तरह चौंकाने वाले हो सकते हैं, जिससे विभाजन और फूट की राजनीति को और बढ़ावा मिलेगा, और यह आश्चर्य की बात नहीं होगी यदि स्थिति "जिसके तड़ में लड्डू उसके तड़ में हम" जैसी न हो जाए?